कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 61 अंक : 06 पृष्ठ : 52 अप्रैल 2015 मूल्यः ₹10

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

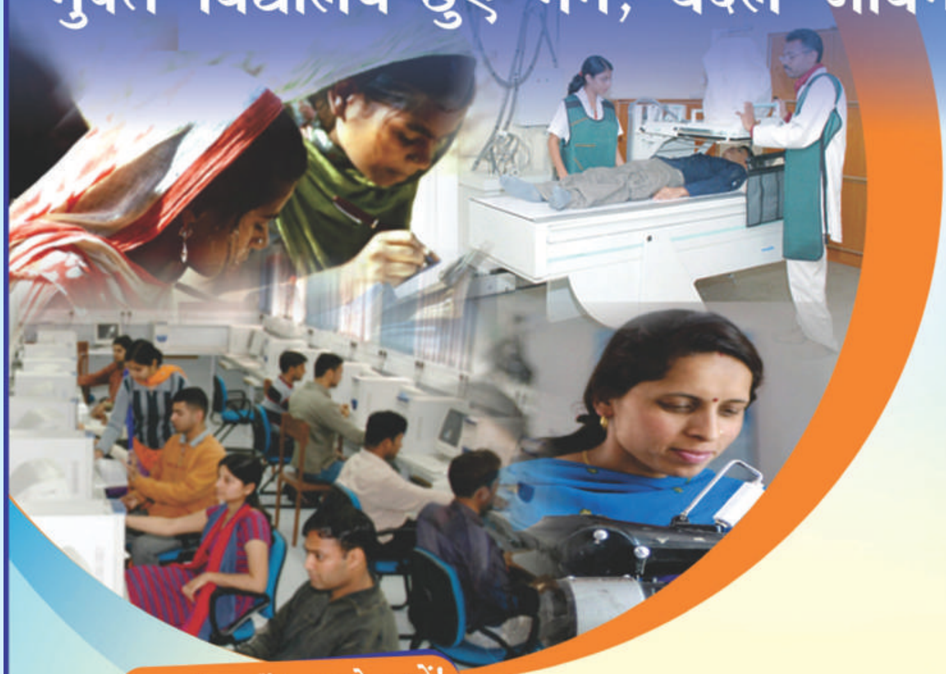

आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें...
मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियां
	पुरुष	महिलाएं	छूट प्राप्त वर्ग	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा–III, V एवं VIII	–	–	–	30 जून (प्रत्येक वर्ष)
• सेकेन्डरी (कक्षा - X) (i) पाँच विषयों के लिए (ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	 ₹ 1350 ₹ 200	 ₹ 1100 ₹ 200	 ₹ 900 ₹ 200	ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ) ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा - XII) (i) पाँच विषयों के लिए (ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	 ₹ 1500 ₹ 230	 ₹ 1250 ₹ 230	 ₹ 975 ₹ 230	ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ) ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			सत्र - 1 : 30 जून (प्रत्येक वर्ष) सत्र - 2 : 31 दिसम्बर (प्रत्येक वर्ष)

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रो, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)
ए–24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री नं. 1800-180-9393; ईमेल : lsc@nios.ac.in वेबसाइट : www.nios.ac.in

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

KH-384/2014

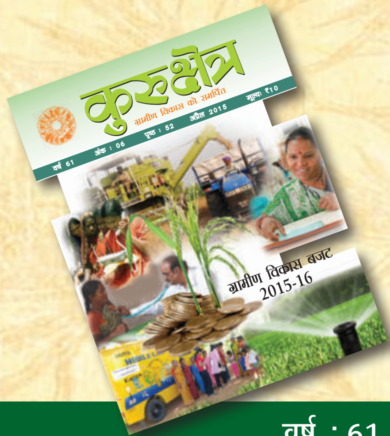

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 61 ★ मासिक अंक : 06 ★ पृष्ठ : 52 ★ चैत्र–वैशाख 1937★अप्रैल 2015

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 011–26100207, फैक्स : 26100207
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

आर्थिक सुधारों वाला बजट — अखिलेश चंद्र — 5

युवाओं की उम्मीदें : बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर — प्रोफेसर हेमंत जोशी — 10

बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक विकास पर बल — ओ.पी. शर्मा — 13

महत्वपूर्ण ग्रामीण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं — मयंक श्रीवास्तव — 18

किसानों को सस्ता ऋण और ऋण चुकाने में भी मदद — शिशिर सिन्हा — 20

तकनीकी उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाएगा यह बजट — बालेन्दु दाधीच — 24

बिजली और कुटीर उद्योगों की मजबूती पर बल — देवेन्द्र उपाध्याय — 27

गांवों के सर्वांगीण विकास पर ज़ोर — सबिता कुमारी — 30

सशक्त कृषि संचार 'प्रति बूंद, अधिक फसल' का आधार — उमाशंकर मिश्र एवं सुबोध कुमार — 33

बजट में पर्यटन विकास पर जोर — नवनीत रंजन — 37

रेल बजट में ढांचागत मजबूती के प्रयास — मनोज श्रीवास्तव — 41

सेहत के लिए फायदेमंद भिंडी — सावित्री यादव — 45

बहुफसली खेती ने बदली किसान की तकदीर — दिव्या श्रीवास्तव — 48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर ले। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

वर्ष 2015–16 के बजट में 2022 तक सबको घर, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर गांव में सड़क, हर गांव में चिकित्सा सुविधा, हर घर में एक को रोजगार और गरीबी खत्म करने का स्वप्न संजोया गया है। इस बजट का मजबूत पक्ष बुनियादी सुविधाओं का विकास है।

बजट में सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की भी कारगर पहल की गई है। साथ ही, बजट में किसानों के हितों का खास ध्यान रखा गया है। न केवल उन्हें ऋण देने तथा ऋण चुकाने में मदद उपलब्ध कराई है। साथ ही, कृषि उपज को बढ़ाने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के तमाम उपाय किए गए हैं। कृषि उत्पादकता, सिंचित क्षेत्र बढ़ाने व कृषि संबंधी योजनाओं की कार्य कुशलता व किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है।

बजट में आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा की प्रासंगिक पहल की गई है। गरीबों के लिए नई बीमा योजनाओं की शुरुआत हुई है। जन–धन योजना को विस्तारित करते हुए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना को उससे जोड़ने का प्रस्ताव है। इस योजना में मात्र 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के दुर्घटना–मृत्यु जोखिम को कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए एक रुपये प्रतिदिन के प्रीमियम पर दुर्घटना–मृत्यु जोखिम पर दो लाख रुपये का कवर दिया जाएगा। साठ साल से अधिक के उम्र की लोगों के लिए अटल पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है जोकि 1 जून 2015 से शुरू होगी।

गांवों को संवारने के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण ढांचागत विकास निधि गठित की जाएगी। 'सबको आवास' देने की योजना के तहत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने आम बजट में गांवों की सेहत व सूरत, दशा और दिशा बदलने की घोषणा की है। बजट में हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ सबको मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा व प्रत्येक घर में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है।

रोजगार वृद्धि के लिए 'स्किल इंडिया' और मेक इन इंडिया' में समन्वय के प्रयत्न किए गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारपरक योग्यता का विकास करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल उन्नयन योजना लाई गई है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) तंत्र की स्थापना की भी घोषणा की गई है। 'मेक इन इंडिया' अभियान से भारत के लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों के सृजन हेतु वैश्विक विनिर्माण केन्द्र भी विकसित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का जाल बिछाकर हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा वर्ष 2022 तक 'सबको आवास' देने का वायदा पूरा किया जाएगा। घरों को पेयजल और शौचालय से लैस किया जाएगा। सभी घरों में बिजली के कनेक्शन होंगे और ऐसे सभी घरों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत छह करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे।

घाटे की खेती को पटरी पर लाने के लिए कई अहम उपायों की घोषणा की गई है। लागत घटाकर उपज बढ़ाने वाली खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करेगी। खेती के लिए मिट्टी की सेहत परखने और फसलों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को आम बजट में खास प्राथमिकता दी गई है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

किसानों की सेहत सुधारने के लिए वित्तमंत्री ने आम बजट में कृषि कर्ज की राशि को 8 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड रुपये कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए यह कर्ज देने की पहल की गई है। रूरल क्रेडिट फंड के लिए भी 15 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार ने 12257 करोड़ रुपये की कृषोन्नति योजना भी शुरू की है।

बजट में बेटियों और महिलाओं के बचाव व सुरक्षा के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बेटियों की सुरक्षा और विवाह के लिए सुरक्षित निवेश आवश्यक है। इसी के मद्देनजर बेटियों के भविष्य को सुकन्या समृद्धि योजना से सुरक्षित और लाभकारी बनाया गया है। इसमें व्यक्ति के निवेश के साथ सरकार भी सहयोग देगी। इसमें निवेश से करों में राहत तो मिलेगी ही, साथ ही मिलने वाला ब्याज करमुक्त रखा गया है।

इस बजट में देश को तरक्की पर ले जाने के ढेर सारे प्रयासों के साथ हर वर्ग के विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। और गरीब, मध्य वर्ग, किसान, युवा, बुजुर्ग, छोटे व्यापारी से लेकर कारपोरेट क्षेत्र सभी को कुछ न कुछ देने का वायदा किया गया है।

आर्थिक सुधारों वाला बजट

—अखिलेश चंद्र

सरकार ने बजट में देश को तरक्की पर ले जाने के ढेर सारे प्रयास किए हैं। साथ ही हर वर्ग के विकास का भी पूरा ध्यान रखा है। गरीबों, मजदूरों एवं बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए तमाम तरह के प्रावधान किए हैं । पूंजी निवेश का दायरा बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है ताकि देशवासियों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उनकी ही पूंजी से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने पहले पूर्ण बजट में गरीब, मध्य वर्ग, कॉरपोरेट क्षेत्र, किसान, छोटे व्यापारी, युवा और बुजुर्ग, सभी को कुछ न कुछ देने का वायदा किया है। वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत मात्र 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने का ऐलान किया है। यह अब तक के इतिहास की सबसे अहम बीमा योजना होगी। इसी तरह अटल पेंशन योजना के तहत 31 दिसंबर, 2015 से पहले खोले गए नए खातों में पांच साल तक प्रतिवर्ष 1000 रुपये का सरकार योगदान देगी। 1000 रुपये खाताधारक जमा कराएगा। वित्तमंत्री ने बजट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की है। इसका प्रीमियम 330 रुपये प्रतिवर्ष या एक रुपये प्रतिदिन से कम होगा। इस योजना में 18 से 50 वर्ष के लोग शामिल होंगे। इसके तहत नैसर्गिक मृत्यु अथवा दुर्घटना पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर होगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने लोकसभा में केंद्रीय बजट

2015–16 प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि विकास से समावेशी विकास होगा। जहां एक ओर बड़ी कारपोरेट और कारोबारी कंपनियों को इसमें भूमिका निभानी है, वहीं दूसरी ओर इसे अधिकतम रोजगार सृजन में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संपूरित करना होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि पीपीएफ में लगभग 3000 करोड़ रुपये और ईपीएफ निधि में लगभग 6000 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशियां पड़ी हैं। इन राशियों के विनियोजन के लिए वित्त विधेयक में अदावाकृत निक्षेप अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया है। इसका उपयोग इनके प्रीमियमों को सब्सिडी देने पर किया जाएगा। कमजोर वर्गों, वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्डधारकों और छोटे व सीमांत किसानों और अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। देश में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सम्मान दिए जाने की जरूरत है जिनकी संख्या लगभग 10.5 करोड़ है। इनमें से एक करोड़ से ज्यादा 80 वर्ष से ऊपर वाले हैं। इनमें से 70 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनका काफी बड़ा प्रतिशत वृद्धावस्था से जुड़ी विकलांगताओं से भी पीड़ित है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायता जीवन साधन उपलब्ध कराने की एक नई योजना शुरू की जाएगी।

वास्तव में इस बजट को 'आर्थिक सुधारों वाला बजट' कहा जाना ज्यादा बेहतर होगा। बजट में हवा–हवाई प्रावधानों को दरकिनार करते हुए तमाम ठोस प्रावधान किए गए हैं, जिससे सालभर के प्रयासों के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार की दिशा में बेहतर परिणाम हासिल हो सकेंगे। वित्तमंत्री ने बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए सरकारी निवेश की घोषणाओं के साथ बजट में कारपोरेट टैक्स को चार वर्षों में घटाकर 25 फीसदी पर ले आने का फैसला किया है। बजट में गरीबों और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं, तो कामगारों को रिटायरमेंट लाभ में विकल्प देने जैसी नवोन्मेषी योजना भी है। काले धन के खिलाफ सख्ती की बात की गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष में

महंगाई दर तकरीबन तीन से 3.5 फीसदी रहेगी, जोकि फिलहाल पांच फीसदी के करीब है। एक अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष के दौरान जीडीपी की सांकेतिक विकास दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि महंगाई दर को समायोजित करने के बाद जीडीपी की वास्तविक विकास दर आठ से 8.5 प्रतिशत के बीच अनुमानित की गई। बजट के अनुसार प्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित बदलावों से राजस्व को होने वाला नुकसान 8,135 करोड़ रुपये होगा। पर अप्रत्यक्ष करों को लेकर जो प्रस्ताव हैं, उनके जरिए 23,383 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की भी बात कही गई है।

बजट में इनकम टैक्स की चर्चा करते हुए वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि टैक्स स्लैब ज्यों का त्यों रखा जाएगा, लेकिन वेतनभोगी वर्ग को परिवहन व्यय (ट्रांसपोर्ट अलाउंस) पर मिल रही कर छूट में राहत दी है। वेतनभोगियों को अब हर माह 800 रुपये के बजाय 1,600 रुपये पर परिवहन व्यय के रूप में कर छूट मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम में हर वर्ष 15,000 रुपये के बजाय 25,000 (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 30,000) रुपये पर आयकर की धारा–80डी में छूट मिलेगी। कुछ विशेष रोग के उपचार के खर्च में पहले 60,000 रुपये तक पर जो छूट मिलती थी, उसे बढ़ा कर 80,000 रुपये कर दिया गया है। पेंशन योजनाओं में विनियोग पर भी साल में 50,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन प्रदान किया गया है। इन सबको जोड़ कर साल में 4,44,200 रुपये की टैक्स फ्री आय बनती है। कारपोरेट जगत को राहत देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इस समय जो 30 फीसदी का कारपोरेट टैक्स लगता है, उसे चार वर्षों की अवधि में घटा कर 25 फीसदी कर दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े कानूनों को सरल कर इस पर लगने वाले तमाम उपकरों को खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर 12.36 फीसदी से बढ़ा कर 12.50 फीसदी और सेवा कर की दर भी 12.36 फीसदी से बढ़ा कर 14 फीसदी कर दी है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए वित्तमंत्री ने सरकारी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए जम्मू व कश्मीर, पंजाब और हिमाचल समेत पांच नए एम्स की सौगात दे दी है। योग संस्थाओं को चैरिटेबल वर्ग में शामिल किया गया है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 33150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ाने की योजना के मद में 600 करोड़ रुपये का इजाफा किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं में 100 करोड़ रुपये से भी कम राशि खर्च की गई है। इसी तरह वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का देश में विशेष सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ परामर्श कर गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी ताकि वृद्धावस्था में उन्हें चिंता नहीं करनी पड़े। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए चल रही कल्याण योजनाओं के कार्यक्रमों में भारी–भरकम आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 30,851 करोड़, जनजाति के लिए 19,980 करोड़ और महिलाओं पर 79,258 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को तवज्जो देते हुए उनके फायदे के लिए वरिष्ठ नागरिक बीमा योजना पर कर छूट दी जाएगी। भविष्य निधि जमा के लिए सरकार ने दो विकल्प ईपीएफ या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का मौका दिया है। वहीं गरीब कर्मचारी जिनकी मासिक आय औसत से काफी कम है, उनके लिए पीएफ में जमा करने या नहीं करने का भी विकल्प होगा। ईएसआई या इरडा के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद को खरीदने का भी विकल्प ऐसे लोगों को सरकार उपलब्ध कराएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर जोर

रेल और सड़क के मद में बजटीय अनुदान बढ़ा दिया गया है। रेलवे के आवंटन में चालू वित्तवर्ष के मुकाबले आगामी वित्त वर्ष के लिए 10050 करोड़ रुपये तो सड़क के लिए 14031 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई। आगामी वित्त वर्ष में सार्वजनिक कंपनियों का पूंजीगत व्यय 3,17,889 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जोकि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 80,844 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2014–15 के मुकाबले आगामी वित्त वर्ष 2015–16 में 70,000 करोड़ रुपये अधिक निवेश की योजना बनाई है। यह निवेश केंद्रीय फंड और केंद्रीय सार्वजनिक इकाइयों से होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए सरकार ने इस बार 42912.65 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन उपलब्ध कराया है। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विशेष एक्सीलरेटेड सड़क विकास कार्यक्रम, नक्सली क्षेत्र में सड़क के लिए राशि भी शामिल है। नौवहन क्षेत्र के लिए 4546.53 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है, जिसमें से 932.79 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता है। इसमें से कुछ राशि सागरमाला परियोजना के लिए भी आवंटित की गई है। सागरमाला परियोजना के लिए अलग से भी 200 करोड़ रुपये की रकम की व्यवस्था की गई है। नागरिक विमानन में एयर इंडिया में इक्विटी इंफ्यूजन के लिए 2500 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन की व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए 61,404 करोड़ रुपये का प्रावधान

बजट में 4000 मेगावाट के पांच अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) की भी घोषणा की गई जिस पर एक लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.1 फीसदी से कम कर 3.9 फीसदी तक लाए जाने से जो राशि बचेगी उसे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर खर्च किया जाएगा। बजट में वित्तमंत्री ने पांच अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) की घोषणा करते हुए कहा कि ये यूएमपीपी प्लग एंड प्ले मोड पर स्थापित की जाएंगी। इन यूएमपीपी की स्थापना में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश बजट में ग्रामीण इलाके में विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 4500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को वर्ष 2022 तक 1.75 लाख मेगावाट तक ले जाने की भी घोषणा की गई। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के समर्थन में कोयले पर लगने वाले उपकर को बढ़ाने का भी ऐलान किया। अब कोयले पर लगने वाले उपकर को 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। आगामी वित्तवर्ष 2015–16 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल 61404.47 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल 6160.73 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। परमाणु ऊर्जा के लिए बजट में 9795 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4000–4000 मेगावाट की थर्मल परियोजना लगाई जाती हैं।

किसानों को दिया तोहफा

सरकार ने खेत–खलिहान की दशा सुधारने का भी विशेष ध्यान रखा है। त्वरित लोकलुभावन योजनाओं के बजाय दूरगामी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उपज की पैदावार का वाजिब मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की बात कही है। इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों के लिए हमारी प्रतिबद्धता बहुत गहरी है। हमने कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण दो प्रमुख कारकों–मिट्टी और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए वित्तमंत्री ने कृषि मंत्रालय की जैविक खेती योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना के वित्तपोषण और उसे सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। वित्तमंत्री ने कहा है कि किसान स्थानीय व्यापारी के शिकंजे में नहीं हैं। लेकिन उनके उत्पाद को अब भी वाजिब दाम नहीं मिलता है। इसके लिए राज्य सरकारों से बात करके सरकार जल्द ही **राष्ट्रीय कृषि बाजार** का गठन करेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन गिरने से सरकार पर दबाव है। इसी तरह सिंचाई सुविधा की बेहतरी के लिए सूक्ष्म सिंचाई को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। किसानों की सेहत सुधारने के लिए वित्तमंत्री ने आम बजट में कृषि कर्ज की राशि को 8 लाख करोड़ से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए यह कर्ज देने की पहल की गई है। रुरल क्रेडिट फंड के लिए भी 15,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। सूखे के मोर्चे पर भी सरकार गंभीर नजर आई। नए बजट में हर किसान के खेत तक सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना इसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 5300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत सूक्ष्म कृषि विकास को 1800 करोड़, एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम को 1500 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मद में 2000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं कृषि को उन्नत बनाने के नाम पर सरकार ने 12257 करोड़ रुपये की कृषोन्नति योजना शुरू की है। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 4500 करोड़, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को 2823 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को 1300 करोड़ और राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन को 835 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

ग्रामीण विकास को लगेंगे पंख

केंद्र सरकार ने बजट में ग्रामीण विकास पर जोर दिया है। इसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन (ग्रामीण और शहरी) के लिए 2505 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें से 210.5 करोड़ उत्तर–पूर्व और सिक्किम के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक हजार 40 करोड़ रुपये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डेवलपमेंट, द कौंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रुरल टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट सपोर्ट टू रुरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बीपीएल सर्वे, ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं। वित्तमंत्री ने बताया कि अभियान के तहत 50 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है। वहीं अमृत महोत्सव के तहत 2020 तक 20 हजार गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। सड़क मार्ग से अब तक नहीं जुड़ी बस्तियों और गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत एक लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी के तहत प्रत्येक गांव में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। अधोसंरचना विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह नाकाफी है। मनरेगा के लिए 34 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि का आवंटन किया गया है। लेकिन इससे ग्रामीण अधोसंरचना जैसे सड़क, नहर और पुलों का कैसे निर्माण किया जाए, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वित्तमंत्री जेटली ने वर्ष 2015–16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण और संरचना विकास कोष की निधियों में 25000 करोड़ रुपये, दीर्घकालिक ग्रामीण कर्ज कोष में 15000 करोड़ रुपये, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण कर्ज रिफाइनेंस निधि के लिए 45000 करोड़ रुपये और अल्पावधिक

आर आर बी रिफाइनेंस निधि के लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया।

शिक्षा के उन्नयन का प्रयास

केंद्र सरकार ने शिक्षा के उन्नयन की दिशा में भी तमाम प्रावधान किए हैं। त्वरित तौर पर सर्व शिक्षा अभियान के बजट में भले कटौती की गई है, लेकिन उसकी भरपाई के लिए दूसरे तमाम प्रयास किए गए हैं। उच्च शिक्षा के विकास पर सरकार ने कई अहम ऐलान किए हैं। कर्नाटक में आईआईटी, धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद को पूरी तरह से आईआईटी में बदलने का भी ऐलान किया गया है। अमृतसर में एक बागवानी अनुसंधान और शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंध संस्थान बनाए जाएंगे। केरल में मौजूदा राष्ट्रीय श्रवण संस्थान को निशक्तता अध्ययन और पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। तीन नए राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बनाने का प्रस्ताव है। इनमें से एक–एक संस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। नगालैंड और ओड़िशा में एक–एक विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान में पिछले साल 24375.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस बार सिर्फ 22 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। मिड डे मील में पिछले साल लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का आवंटन था। इस बार सिर्फ 8900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं दूसरी तरह आम बजट में सरकार ने कहा है कि हर बच्चे के लिए पांच किलोमीटर के भीतर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाएगा। इसके तहत 80 हजार माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड और 75 हजार उच्च प्राथमिक –स्तर के स्कूलों को प्रोन्नत करके सीनियर माध्यमिक स्तर करने की जरूरत जताई है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा में 6705 करोड़, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 1155 करोड़, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 1155 करोड रुपये आवंटित किए गए हैं।

आंतरिक सुरक्षा होगी मजबूत

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में भी तमाम प्रयास किए हैं। रक्षा बजट में 10.9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। जबकि आंतरिक सुरक्षा के बजट में बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले महज 4.5 फीसदी की ही बढ़ोतरी की गई। इस तरह रक्षा क्षेत्र को मिले 2.46 लाख करोड़ रुपये तो आंतरिक सुरक्षा के लिए 62124 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रबंधन के बजट में 10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वित्तमंत्री ने उम्मीद जताई है कि मेक इन इंडिया अभियान और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ा कर 49 फीसदी किए जाने से इस क्षेत्र की चुनौतियों से लड़ा जा सकेगा। बजट में सीआरपीएफ को 14089.38, एनएसजी को 636.01, बीएसएफ को 12517.82, आईटीबीपी को 3736.47, सीआरपीएफ को 5196.65, असम राइफल्स को 3846.66, आईबी को 1270.40 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी

वित्तमंत्री ने कहा कि लगभग 5.77 करोड़ छोटे व्यवसाय वाली इकाइयां हैं। इनमें से अधिकतर वैयक्तिक स्वामित्व की हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवा व्यवसाय चलाती हैं और इनमें 62 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। ये मेहनतकश उद्यमी पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर हैं और उनके लिए ऋण की औपचारिक प्रणालियों तक पहुंच बनाना असंभव नहीं लेकिन मुश्किल अवश्य है। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये की निधि और 3000 करोड़ रुपये की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित एजेंसी (मुद्रा) के सृजन का प्रस्ताव किया।

अटल नवाचार मिशन की स्थापना

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन की स्थापना करने की मंशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अटल नवाचार मिशन (एआईएम) एक नवाचार संवर्धन मंच होगा जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और भारत में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा वैज्ञानिक शोध की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाया जाएगा। इसके जरिए भारत के लिए विश्वस्तरीय नवाचार केंद्रों के नेटवर्क को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए एक सौ पचास करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी।

बजट में खास–खास

- सभी भारतीयों विशेषकर गरीबों व वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत।
- अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा।
- कमजोर वर्गों, वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्डधारकों और छोटे व सीमांत किसानों और अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी देने की योजना।
- अल्पसंख्यकों के लिए एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका योजना 'नई मंजिल' की शुरुआत की जाएगी।

किसे कितना मिला बजट

- कृषि उन्नति योजना के लिए आम बजट में 3257 करोड़

रुपये का प्रावधान किया गया है। यह खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। मृदा सेहत कार्ड, कृषि सहयोग एवं कृषि विपणन योजना तथा कृषि विस्तार, बागवानी विकास व मूल्य स्थिरीकरण कोष पर राष्ट्रीय मिशन और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन।

- डेयरी विकास अभियान के लिए बजट में 481 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के तहत अतिरिक्त दूध को खरीदना है। राष्ट्रीय डेयरी प्लान के लिए प्रमुख कार्यक्रम, डेयरी उद्यमिता योजना और डेयरी विकास योजना।
- नीली क्रांति के लिए 411 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- फसल बीमा के लिए आम बजट में 2589 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए 3295 करोड़ रुपये बजट में अलग से रखे गए हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर के लिए बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 'मेक इन इंडिया' के लिए 310 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक निवेश गंतव्य के तौर पर भारत को बढ़ावा देना और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करते हुए भारत को एक विनिर्माण केन्द्र (मैन्युफैक्चरिंग हब) के रूप में स्थापित करना है, ताकि उनके उत्पाद भारत में ही बनाए जा सकें।
- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन के लिए 910 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 'डिजिटल इंडिया' के लिए 2510 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। यह कार्यक्रम सुशासन, वर्चुअल क्लासरूम, साइबर सुरक्षा, आम जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पर केन्द्रित हैं।
- स्वच्छ ऊर्जा पहलों हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के लिए 4700 करोड़ रुपये।
- स्वदेश दर्शन घरेलू पर्यटन सर्किट के लिए 600 करोड़ रुपये।
- भारत यूआईडी प्राधिकरण के लिए 2000 करोड़ रुपये।
- कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के लिए 1500 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण एवं शहरी विकास दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 4230 करोड़ रुपये।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 29420 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4134 करोड़ रुपये।
- मेट्रो परियोजनाओं के लिए 8260 करोड़ रुपये। इनमें दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोच्चि, जयपुर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर शामिल हैं।
- 100 स्मार्ट सिटी के लिए 5899 करोड़ रुपये।
- नमामि गंगे–2100 करोड़ रुपये।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया कोष हेतु 1000 करोड़ रुपये।
- स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 7824 करोड़ रुपये।
- स्कूली शिक्षा के लिए 17672 करोड़ रुपये और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हेतु100 करोड़ रुपये।
- सभी के लिए आवास–शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ आवास।
- आजीविका के लिए परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार।
- गांवों में फैले 1,54,000 उपस्थित केंद्रों वाले डाक नेटवर्क का सामान्य वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- सोना खरीदने के लिए विकल्प के तौर पर सरकारी स्वर्ण बांड स्कीम बनाना। भारतीय सोने के सिक्के बनाने की दिशा में कार्य करना, जिसके अग्र भाग में अशोक चक्र होगा।
- जम्मू–कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश और असम में नए एम्स की स्थापना, बिहार में एम्स जैसे दूसरे संस्थानों की स्थापना।

बजट का अंकगणित

- वित्तवर्ष हेतु आयोजना भिन्न व्यय 13,12,200 करोड़ रुपये अनुमानित।
- आयोजना व्यय 4,65,277 करोड़ रुपये अनुमानित।
- कुल व्यय 17,77,477 करोड़ रुपये अनुमानित।
- सकल कर प्राप्तियां 14,49,490 करोड़ रुपये अनुमानित।
- राज्यों को अंतरण 5,23,958 करोड़ रुपये अनुमानित।
- आगामी वित्तवर्ष के लिए कर–भिन्न राजस्व 2,21,733 करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

(लेखक आर्थिक पत्रकार हैं।)
ई–मेल: acyinp@gmail.com

युवाओं की उम्मीदें : बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर

—प्रोफेसर हेमंत जोशी

स्पष्ट है कि नई सरकार के नए बजट में भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक बातें कही गई हैं। यह बात और है कि इन सब घोषणाओं के बावजूद रोजगार के कितने अवसर निकलेंगे, युवा भारत की तस्वीर कितनी बदलेगी यह तो अगले बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से ही पता चल पाएगा। दरअसल, इस साल के बजट में वास्तविक विकास से अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा उस दृष्टि से संबद्ध है जो नई सरकार नए भारत के निर्माण को लेकर दर्शाना चाहती है।

वर्ष 2015–16 का बजट सदन में रखते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से एक है। हमारे देश की कुल आबादी का 54 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। आवश्यक है कि हमारे युवा 21वीं शताब्दी की नौकरियों के लिए शिक्षित और रोजगार पर रखे जाने योग्य हों। इससे पहले वह बजट की प्रमुख बातें बताते हुए यह भी कह चुके थे कि हमारी दो–तिहाई आबादी 35 वर्ष से कम उम्र वालों की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे युवाओं को उचित रोजगार प्राप्त हो, हमें भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य को लेकर चलना होगा। 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं।

बजट प्रावधानों के अनुसार नई सरकार की 'मेक इन इंडिया' योजना से अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के प्रयासों को गति देने के लिए इस बजट में जो दो महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। उनमें से पहला है– स्किल इंडिया परियोजना जिसके तहत युवाओं को विभिन्न कौशल सिखलाए जाएंगे और दूसरा फैसला इस काम को अंजाम देने के लिए कौशल उन्नयन और नवोन्मेष का एक नया मंत्रालय गठित करने का है। इस मंत्रालय के लिए 1543.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्किल इंडिया

आज भी हमारे सक्षम कार्यबल के 5 प्रतिशत से भी कम को ऐसा औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो पाता है कि वे रोजगार पर रखे जाने योग्य हों और रोजगार में बने रह सकें।

शीघ्र ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के जरिए एक राष्ट्रीय स्किल मिशन का शुभारंभ किया जाने वाला है। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे कौशल संबंधी कार्यक्रमों को समेकित किया जाएगा तथा हमारी सभी 31 क्षेत्रीय कौशल परिषदों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक डिजिटल वाउचर कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है जिससे प्रत्येक योग्यता प्राप्त छात्र किसी प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदाता से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा।

भारत की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अभी भी गांवों में निवास करता है। अतः ग्रामीण युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करना भारत की आबादी में युवाओं की इस अधिक भागीदारी से लाभ उठाने की कुंजी है। इसे ध्यान में रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है। वैसे देखा जाए तो यह पहले से चले आ रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का ही नया स्वरूप है। इस स्कीम के लिए 1,500 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है। उसका उद्देश्य 2017 तक 15 वर्ष से अधिक उम्र के 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिला पाना है।

सभी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र अपनी पसंद की उच्च शिक्षा बिना किसी धनाभाव के प्राप्त कर सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी छात्रवृत्तियों और साथ ही शिक्षा ऋण स्कीमों के आद्योपांत प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी युक्त छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे।

राष्ट्रीय जीविका मिशन

राष्ट्रीय जीविका मिशन के तहत भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनका लाभ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिलेगा। इसके तहत मनरेगा, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विभिन्न योजनाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इन सभी से संबद्ध मंत्रालयों के खाते में सरकार ने जो वृद्धि की हैं, उनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा।

हालांकि प्रधानमंत्री ने मनरेगा की विफलता पर पिछली सरकार पर कटाक्ष तो किए लेकिन इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 34,699 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटन किया है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार में मदद करने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी गरीब रोजगार के बगैर न रह जाए। हम मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वर्ष के दौरान कर उछाल से कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आशा है। यदि ऐसा हुआ तो बजटीय आवंटन से मनरेगा के लिए 5000 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

इसी प्रकार, उन अल्पसंख्यक युवाओं को समर्थ बनाने के लिए जिनके पास औपचारिक स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं होता और वे कोई रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, इस वर्ष 'नई मंजिल' नामक एकीकृत शिक्षा और आजीविका स्कीम आरम्भ की जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए आवंटन संरक्षित किया जा रहा है और वर्ष 2015–16 के अनुमानित बजट में इसे 3,738 करोड़ रुपये ही रखा गया है।

सेतु (स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग) परियोजना

इस बार अटल नवोन्मेष मिशन की स्थापना की घोषणा भी की गई है। अटल नवोन्मेष मिशन एक नवोन्मेष संवर्धन मंच होगा। इसमें शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को आकर्षित करेगा। यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्रों में दोहराव के लिए श्रेष्ठ परंपराओं को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में इस प्रयोजन के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की जाएगी।

भारत के पास सुप्रतिष्ठित और विश्वस्तरीय आईटी उद्योग है। इसके पास लगभग 150 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व है और यह लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब हम इसमें नवउद्यमियों की रुचि देख रहे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, विचारों से मूल्यों का सृजन और उन्हें कार्यक्रमों एवं आरोह्य उद्यमों तथा कारोबार में बदलना, हमारे युवा वर्ग को कार्य में लगाना और हमारे देश का समावेशी एवं स्थायी विकास करना हमारी कार्यनीति का मुख्य आधार है। वैश्विक पूंजी जुटाने की अधिक उदार प्रणाली, हमारे उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नत सुविधाएं, आधार पूंजी और विकास के लिए वित्तपोषण और कारोबार करने की सुगमता जैसे प्रयासों से लाखों रोजगार और कई बिलियन डालर का सृजन किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से सरकार सेतु (स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग) नामक तंत्र की स्थापना कर रही है। सेतु एक प्रौद्योगिक–वित्तीय, इन्क्यूबेशन और सुविधा प्रदान करने वाला कार्यक्रम होगा जो विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करेगा। इस प्रयोजन के

लिए नीति आयोग में आरंभिक तौर पर 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इसी प्रकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को और सुसंगत बनाने के लिए सरकार ने रोजगार कार्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार की युवाओं के रोजगार की चिंता इस बात से भी साबित होती है कि वित्तमंत्री के भाषण में रोजगार और शिक्षा शब्द 30–30 बार और युवा शब्द 18 बार इस्तेमाल किया गया है।

शिक्षा

हालांकि रोजगार का संबंध शिक्षा से कहीं अधिक उत्पादकता और अर्थव्यवस्था से होता है, पर यह भी सर्वज्ञात है कि शिक्षा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का साधन है। इस नजरिए से सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सुधार की कई योजनाएं तैयार की हैं। शिक्षा के अलावा कौशलों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है।

अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि अपने युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें शिक्षित करना और कौशल संपन्न बनाना एक ऐसी वेदी है जिसके सामने हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे के लिए 5 किमी. के भीतर एक सीनियर सेकेन्डरी स्कूल हो, हमें 80,000 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन करने तथा अन्य 75,000 जूनियर माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्तर तक करने की आवश्यकता है। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा में गुणवत्ता तथा शिक्षण परिणामों की दृष्टि से सुधार हो।

वित्तवर्ष 2015–16 में जम्मू–कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जाए। बिहार में आयुर्विज्ञान को बढ़ावा देने के मद्देनजर, इस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अन्य संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। कर्नाटक में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी) स्थापित करने तथा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को एक परिपूर्ण आई.आई.टी में अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है। अमृतसर में बागवानी अनुसंधान तथा शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। जम्मू–कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए जाएंगे। केरल में मौजूदा राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण संस्थान को निःशक्तता अध्ययन तथा पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। तीन नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है जिनमें से एक–एक संस्थान क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा तथा नगालैंड और ओडिशा में एक–एक विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

इन सभी कदमों से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उम्मीद है कि आगामी तीन से चार वर्षों के दौरान देश में शिक्षित, प्रशिक्षित एवं कुशल कारीगरों का एक बड़ा मानव संसाधन तैयार होगा जो देश की अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त उछाल ला सकेगा और विकास के अप्रत्याशित प्रतिमानों को प्राप्त करने में देश की मदद करेगा।

(लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक विकास पर बल

–ओ.पी. शर्मा

बजट आर्थिक विकास की नीति के साथ अर्थव्यवस्था की दिशा भी निर्धारित करता है। एक प्रकार से बजट अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। इस हिसाब से यह देखा जाना चाहिए कि इस बजट में आर्थिक समस्याओं पर समाधान के क्या कदम उठाए गए हैं? इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में जो कमजोर आर्थिक घटक हैं, उन्हें सुधारने के क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी, 2015 को केन्द्रीय बजट 2015–16 लोकसभा में पेश किया। जेटली द्वारा पेश किया गया यह इस वित्तवर्ष का पूर्णकालिक बजट है। इससे पहले उन्होंने जुलाई माह में वित्तवर्ष 2014–15 का बजट पेश किया था। ताजे आर्थिक सर्वेक्षण पर नजर डाले तो अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने लगा है। जीडीपी वृद्धि दर 2011–12 आधार वर्ष के अनुसार 2014–15 में 7.4 प्रतिशत हो गई है। इसके 2015–16 में 8.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। हालांकि दुनिया में मंदी का माहौल है किंतु भारत में जीडीपी वृद्धि को दो अंकों में पहुंचाने का वातावरण तैयार किया जा रहा है। अगर भारत की जीडीपी वृद्धि दहाई अंक को पार कर जाती है तो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बड़ी सीमा तक कम हो सकेगी। भारत के पास 340 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। रुपया मजबूत है और महंगाई काबू में है। पिछले वर्षों में विदेशी व्यापार पर मंदी का असर था। वित्तवर्ष 2012–13 में निर्यात वृद्धि और 2013–14 में आयात वृद्धि दर ऋणात्मक थी। अप्रैल–दिसम्बर 2014–15 में विदेशी व्यापार की स्थिति सुधरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऐतिहासिक घटी इससे भारत में वित्तीय अनुशासन की स्थिति बनी। चालू खाता घाटा भी कम हुआ है। सेंसेक्स ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचकों के सुधरने से विदेशी निवेशकों का दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति अनुकूल होगा।

आर्थिक चुनौतियां

अच्छे दिन दिखाने के आर्थिक सूचकों के बीच कई आर्थिक समस्याएं ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था में मुंह बाएं खड़ी हैं। आर्थिक विषमता मुखर समस्या है। धनी और गरीब के बीच खाई को पाटा नहीं जा सका है। धनी बहुत अधिक धनी हुआ है और गरीब की आय अपेक्षित नहीं बढ़ी है। आर्थिक विषमता का कारण क्षेत्रीय विषमता भी है। भारत के कई राज्य विकास के मामले में पीछे हैं। क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास में पिछड़ने से लोग आर्थिक विषमता से

ग्रसित होते हैं। भारत विश्व का युवा देश है। यहां की आबादी में युवा अधिक हैं किंतु ग्रामीण आबादी अधिक है। गांवों में युवा बड़ी संख्या में हैं। आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका घटने से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घट गए हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी मुखर हो गई है। भारत आर्थिक विकास में तो तीव्रता से बढ़ रहा है किंतु सामाजिक विकास स्थिति में कमजोर है।

भारत ने विगत वर्षों में आर्थिक प्रगति तो की किंतु वैश्विक आर्थिक सूचकों में भारत की स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है। विश्व के कुल विदेश व्यापार में भारत का भाग अभी भी बहुत कम है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी अधिक आकर्षित नहीं किया जा सका है। बढ़ता विदेशी ऋण अधिक विदेशी मुद्रा भण्डार की महत्ता को घटा देता है। भारत की अर्थव्यवस्था समानांतर अर्थव्यवस्था के घेरे में है। काली अर्थव्यवस्था के चलते प्रासंगिक आर्थिक नीतियां प्रभावी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पाती हैं। भारत ढाई दशकों से आर्थिक उदारीकरण के मार्ग पर है। अर्थव्यवस्था में भारी संरचनात्मक बदलाव किए जा चुके हैं। आर्थिक सुधारों की गति अभी भी जारी है। इस दौर में आर्थिक सुधारों से आर्थिक समस्याओं के समाधान के प्रयत्न किए गए हैं।

विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मौजूद समस्याओं के समाधान आवश्यक हैं। बजट आर्थिक विकास की नीति के साथ अर्थव्यवस्था की दिशा भी निर्धारित करता है। एक प्रकार से बजट अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। इस हिसाब से यह देखा जाना चाहिए कि इस बजट में आर्थिक समस्याओं पर समाधान के क्या कदम उठाए गए हैं? इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15 में जो कमजोर आर्थिक घटक हैं, उन्हें सुधारने के क्या कदम उठाए गए हैं?

बुनियादी सुविधाओं पर जोर

वित्तवर्ष 2014–15 में प्रधानमंत्री जन–धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पारदर्शी कोयला नीलामी आदि रेखांकित की जाने वाली उपलब्धियां हैं। जहां जन–धन योजना में करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए वहीं स्वच्छ भारत अभियान को आंदोलन की तरह क्रियान्वित किया गया। जन–धन योजना के निर्धारित लक्ष्य नियत समय में पूरे कर लिए गए। बजट में इन योजनाओं को और अधिक मजबूती प्रदान की गई है। बजट की महत्वपूर्ण बात देशवासियों को बुनियादी सुविधाओं पर अधिक बल देना है। वर्ष 2022 तक सबके लिए घर, हर घर में शौचालय और सब घरों में बिजली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे बड़ी बात 2022 तक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित करना है। गांव और शहर के बीच भेद खत्म करने की बात कही गई है। गांव और शहर में एक जैसी संचार सुविधा का विकास किया जाएगा। हर गांव में मेडिकल सुविधा होगी। ज्यादा स्कूल खुलेंगे। हर पांच किलोमीटर के दायरे में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल होगा। ये सब ऐसे कदम हैं अगर वे लागू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से देशवासियों को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे।

गांवों की सुध

बजट में गांवों की दशा सुधारने की कारगर पहल है। सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2022 तक गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य है। इसके अलावा गांवों के विकास की योजनाओं में आवंटन बढ़ाया गया है। कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का आकार 33 करोड़ रुपये से छह गुना बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना की घोषणा की गई है। सिंचाई योजना के लिए 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए 3500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। किसानों को कृषि ऋण के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गांवों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 2022 तक रोजगार की बात कही गई है। मनरेगा के लिए 34699 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में मत्स्य क्रांति पर बल है। देसी और समुद्री मत्स्य पालन के लिए बजट दस गुना बढ़ाकर 411 करोड़ रुपये किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

बजट में आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा की प्रासंगिक पहल की गई है। गरीबों के लिए नई बीमा योजनाओं की शुरुआत हुई है। जन–धन योजना वालों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना में मात्र 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के दुर्घटना–मृत्यु जोखिम को कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की घोषणा की गई है। इसके अन्तर्गत 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए एक रुपये प्रतिदिन के प्रीमियम पर दुर्घटना, मृत्यु जोखिम पर दो लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा। साठ साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें एक हजार रुपये सरकार देगी और एक हजार रुपये व्यक्ति को देना होगा। साठ साल की उम्र के बाद अगले पांच वर्ष तक सरकार एक हजार रुपये देगी। भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति कमजोर है। बहुत कम लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं। जनाधिक्य का एक कारण सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी है। बजट में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में की गई पहल से बड़ी आबादी के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने की संभावना है।

मेक इन इण्डिया को गति

केन्द्र सरकार मेक इन इण्डिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रयत्नशील है। विनिर्माण और निवेश ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत को विश्व में आर्थिक ताकत के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में भारत की विशिष्ट पहचान बन चुकी है। विश्व अर्थव्यवस्था के मंदी से उभरने के बाद सेवा क्षेत्र फिर से जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने में भूमिका निभाएगा। कृषि में भारत के खाद्यशक्ति के रूप में उभरने की क्षमता है। केन्द्र सरकार ने 2014–15 से मेक इन इण्डिया की शुरुआत की है। बजट में मेक इन इण्डिया को गति देने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। उद्योगों को बढ़ाने के लिए कारपोरेट टेक्स अगले पांच वर्षों के दौरान 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। इससे निवेश के विकास और अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। कर की दर कम होने से उत्पादन लागत में कमी होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 20000 करोड़ रुपये के निवेश व अवसंरचना निधि की स्थापना की गई है। मेट्रो परियोजनाओं के लिए 8260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश वृद्धि के लिए टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड की घोषणा की गई है। आवास व शहरी विकास के लिए 22407 करोड़ रुपये, सड़कों के लिए 14031 करोड़ रुपये, रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 10050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगार सृजन

उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से रोजगार अवसर सृजित होंगे। भारत में युवा शक्ति अधिक है, उन्हें रोजगार की अधिक दरकार है। देश में रोजगार मांगने वालों की तादाद हर साल 2.3 प्रतिशत से बढ़ रही है जबकि रोजगार में केवल 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। भारत में 2022 तक बेरोजगारी समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोजगार वृद्धि के लिए 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इण्डिया' में समन्वय के प्रयत्न किए गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग को 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ग्रामीण छात्रों में रोजगारपरक योग्यता का विकास करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल उन्नयन योजना लाई गई है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) तंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। मेक इन इण्डिया अभियान से भारत के लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों के सृजन हेतु वैश्विक विनिर्माण केन्द्र विकसित किया जाएगा।

कालाधन पर मार

कालाधन बड़ी समस्या है। इसने अर्थतंत्र की जड़ें खोखली कर रखी हैं। इसे निकालने की कोशिश की गई किंतु यह घटने के स्थान पर बढ़ता ही गया। पिछले वर्षों से यह ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। बजट में देश के भीतर और विदेश में जमा कालाधन पर मार की गई है। आय और सम्पत्ति छुपाने तथा विदेशी सम्पत्ति के संबंध में कर वंचना के लिए 10 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। कालाधन के अपराधों को संगीन अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराधी के लिए आय और सम्पत्ति की मौजूदा दर से 300 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार कालाधन पर बिल लाएगी। बेनामी लेन–देन विधेयक भी पेश होगा। नये विधेयक में आयकर विवरणी दाखिल करने और अधूरी जानकारी के दाखिल करने पर 7 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान होगा। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों के मामले में इस विधेयक के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। फेमा 1999 और धनशोधन कानून 2002 में बदलाव होगा। एक लाख से अधिक की खरीद और बिक्री के लिए पेन अनिवार्य कर दिया गया है। 20 हजार से अधिक के लेन–देन नकद किए जाने पर रोक लगा दी गई है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से व्यापार पर जोर दिया गया है। सरकार जल्दी ही गोल्ड बॉण्ड लांच करेगी। इन पर निश्चित ब्याज मिलेगा। इसके अलावा भारत की छाप वाले स्वर्ण सिक्के जल्दी ही बाजार में आएंगे। अगर कालाधन पर अकुंश लगता है या निकलता है तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। कालाधन के खत्म होने से आर्थिक नीतियां विकास दर को बढ़ाने में अधिक सहायक होंगी। देश में अपराधवृत्ति है चाहे यह धन्ना सेठों के करचोरी व मिलावट के रूप में हो या फिर लोगों द्वारा किए गए अपराध। इनकी पुष्टि आयकर छापे और पुलिस विभाग द्वारा जारी अपराध आंकड़ों से होती है।

कड़े कदम

बजट में सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। इससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2 प्रतिशत सेस तय किया गया है। सभी टैक्स वाली सुविधाओं पर यह सेस लगेगा। अमीरों से वेल्थ टैक्स

हटा दिया गया है किंतु एक करोड़ रुपये से अधिक कर योग्य आय वाले धनिकों पर 2 प्रतिशत का सरचार्ज लगा दिया गया है। आय कर की दर और स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड की घोषणा की गई है। हेल्थ इंश्योरेंस पर 80डी में छूट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें भी 30000 रुपये की कटौती मिलेगी। गंभीर बीमारी पर खर्च के लिए 60000 रुपये की कटौती सीमा बढ़ाकर 80000 रुपये कर दी गई है। आश्रित विकलांग व्यक्ति के इलाज के लिए कटौती सीमा 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी गई है। गंभीर विकलांगता की दशा में कटौती सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। परिवहन भत्ते पर मासिक कर छूट 800 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई है। वेतनभोगी वर्ग को आयकर में राहत दी गई है, इस राहत का मार्ग खपत केन्द्रित नहीं बचत केन्द्रित है।

प्रासंगिक पहल

बजट में बेटियों और महिलाओं के बचाव व सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बेटियों की सुरक्षा और विवाह के लिए सुरक्षित निवेश आवश्यक है। बेटियों के भविष्य को सुकन्या समृद्धि योजना से सुरक्षित और लाभकारी बनाया गया है। इसमें व्यक्ति के निवेश के साथ सरकार भी सहयोग देगी। इसमें निवेश से करों में राहत तो मिलेगी ही, साथ ही मिलने वाला ब्याज करमुक्त रखा गया है। देश की आधी आबादी सुरक्षित रहे, इसके लिए महिलाओं के बचाव, सुरक्षा, जागरुकता, महिलाओं की पैरवी के कार्यक्रमों के लिए निर्भया फण्ड में 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

अर्थव्यवस्था पर सब्सिडी का बड़ा बोझ है। सब्सिडी को कम तो नहीं किया गया है किंतु इसके सदुपयोग के कदम उठाए गए हैं। सब्सिडी के लिए 'जाम' अर्थात जन–धन योजना, आधार और मोबाइल की शुरुआत की गई है। 20 हजार करोड़ रुपये की पूंजी और तीन हजार करोड़ रुपये की गारण्टी मनी के साथ एमएसएमई के लिए 'मुद्रा बैंक' (माइक्रो यूनिट डवलपमेंट एण्ड रिफाइनेंस एजेंसी) की घोषणा की गई है। मुद्रा बैंक उन उद्यमियों की वित्तीय जरूरतें पूरी करेगा जो अभी बहुत ऊंची दरों पर उधारी लेते हैं। इस बैंक से स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

बजट में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल इण्डिया, महिला उद्यमिता, खेल प्रशिक्षण आदि के विकास की कारगर पहल की गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू और आन्ध्र प्रदेश में आईआईएम, कर्नाटक में आईआईटी और आईएमएस धनबाद को पूर्ण आईआईटी का दर्जा, पांच राज्यों जम्मू–कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम में एम्स खुलेंगे और राजस्थान, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में नेशनल फार्मा इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम को तीव्र गति देने के लिए नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पूरे देश में फैलाया जाएगा। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 'नई मंजिल' योजना के लिए 3738 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में 'ई–बिज' की घोषणा की गई है। इसमें नये व्यापार के लिए आवश्यक सभी जानकारी एक वेबपोर्टल पर होगी। केन्द्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग की ओर से ई–बिज वेबपोर्टल का उद्देश्य व्यापार करना आसान बनाने के मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है।

दृष्टिकोण

विश्व अर्थव्यवस्था भले ही मंदी से उभर नहीं सकी हो किंतु भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से दौड़ती दिख रही है। भारत दहाई अंक की विकास दर अर्जित करने की स्थिति में है किंतु सामाजिक विकास की स्थिति ने आर्थिक विकास को प्रभावित कर रखा है। इस बजट का मजबूत पक्ष बुनियादी सुविधाओं का विकास है। 2022 तक सबको घर, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर गांव में सड़क, हर गांव में चिकित्सा सुविधा, हर घर में एक को रोजगार, गरीबी खत्म का स्वप्न संजोया गया है। इन स्वप्नों के साकार होते ही भारत विकसित देशों की श्रेणी में होगा। बजट में सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की कारगर पहल है। 'मेक इन इण्डिया' और 'स्वच्छ भारत' अभियान नई सरकार के दो ऐसे नए कदम हैं जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा दे सकते हैं। मगर इन योजनाओं की सफलता के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। एक बार आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास गति पकड़ ले तो भारत विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा। आर्थिक उदारीकरण के पच्चीस सालों में सेवा क्षेत्र पर बल रहा और ग्रामीण विकास को भी साथ लेकर चला गया किंतु उद्योग और विनिर्माण पिछड़ गया। 'मेक इन इण्डिया' में विनिर्माण पर भारी बल है। इसके साथ केन्द्र सरकार बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दे रही है। उम्मीद है कि केन्द्र सरकार की बजट में की गई नई पहल 'लोगों के अच्छे दिन' में चरितार्थ होगी।

विभागाध्यक्ष, आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंध विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सवाई माधोपुर (राजस्थान)
ई–मेल : opsomdeep@yahoo.com

SPACE IAS उपेन्द्र अनमोल

(सुप्रसिद्ध प्रशासनिक मार्गदर्शक)

पिछले 10 वर्षों में 519 से अधिक UPSC में चयनित अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन

10 वर्षों से पूरे देश में GENERAL STUDIES में सबसे चर्चित रहे शिक्षक

उपेन्द्र अनमोल सर के नेतृत्व में

Batch starts on 11 APRIL

GS

FOUNDATION

Batch starts on 11 APRIL

उपेन्द्र अनमोल

(सुप्रसिद्ध प्रशासनिक मार्गदर्शक) एवं टीम

Editors :

Innovation Today

Science Focus

Economic Progress

Female Today

- पूरे देश में एक मात्र शिक्षक, जो पूरे General Studies के सभी भागों पर एक समान पकड़ रखते हैं।
- Basics से लेकर Advanced Understanding को सुनिश्चित करने वाले एक मात्र शिक्षक
- Answer Writing, Interview और Essay Writing की सर्वश्रेष्ठ कला विकसित करने वाले एकमात्र शिक्षक

उपेन्द्र अनमोल सर द्वारा लिखी गयी बुक

Inner Voice of Science and Technology को Science & Technology and Earth Science Ministry के द्वारा Science की Reference book माना गया है।

A-35-36, 203, 2nd Floor, Bhandari House, Above Post Office, Mukherjee Nagar

Mob. : 9136360007, 8802678660

KH-386/2014

महत्वपूर्ण ग्रामीण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

—मयंक श्रीवास्तव

आर्थिक रफ्तार से भरपूर, लेकिन जनता से नहीं दूर। शायद यही इस बजट का संदेश है। इस बजट में तमाम घोषणाएं की गई हैं लेकिन लोक-लुभावन घोषणाओं से सरकार ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया है और दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाया है। 'मेक इन इंडिया' पर जोर होने के बावजूद भी इस बजट में आम आदमी यानी ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ देने का प्रयास वित्तमंत्री ने किया है। इस बजट में घोषित तमाम योजनाओं पर डालते हैं एक नज़र

भारत के वर्तमान वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बहुप्रतीक्षित पूर्ण बजट देश को समर्पित किया जो प्रधानमंत्री के विज़न 'मेक इन इंडिया' को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में ही यह बताने का प्रयास किया कि पिछली सप्रंग सरकार से विरासत में मिली जर्जर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ''आर्थिक रफ्तार से भरपूर, लेकिन जनता से नहीं दूर,'' शायद यही इस बजट का संदेश है। इस बजट में तमाम घोषणाएं की गई हैं लेकिन लोक लुभावन घोषणाओं से सरकार ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया है और दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाया है। 'मेक इन इंडिया' पर जोर होने के बावजूद भी इस बजट में आम आदमी यानी ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ देने का प्रयास वित्तमंत्री ने किया है।

अटल पेंशन योजना

वित्तमंत्री ने एक नई पहल के तहत इस बजट में एक नई योजना, 'अटल पेंशन योजना' की घोषणा की जो एक जून, 2015 से अस्तित्व में आएगी। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार की योजना है जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। यह योजना खासकर के उन खाताधारकों के लिए है जो कानूनी रूप से किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन नागरिकों के लिए है जो नई पेंशन योजना (एन. पी. एस.) का लाभ लेना चाहते हैं। इसके तहत जितना योगदान पेंशन बचत के लिए जनता करेगी उसका आधा हिस्सा (50 प्रतिशत) सरकार की तरफ से (अधिकतम 1000 रुपये का) सालाना योगदान दिया जाएगा। मसलन जनता नई पेंशन स्कीम के तहत खाता खोलती है और दो हजार रुपये सालाना जमा करना है तो इसमें एक हजार रुपये सरकार अपनी तरफ से देगी। केंद्र ने अगले पांच साल तक यह योगदान करने की बात कही है लेकिन इसका लाभ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा

जो कर का भुगतान नहीं करते और 31 दिसम्बर, 2015 तक पेंशन खाता खोलेंगे। यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के नागरिकों के लिए है। इस योजना के लाभार्थियों को 60 वर्ष तक योगदान के आधार पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये की निश्चित राशि प्रदान की जाएगी जोकि उम्र के साथ परिवर्तित होगी। इसमें योगदान की अवधि अधिकतम 20 वर्ष होगी। पहले से अस्तित्व में चल रही स्वावलंबन योजना के सब्सक्राइबर इस योजना में शामिल हो जाएंगे। इस योजना में मिलने वाले लाभ को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है।

यह उदाहरण उन स्थितियों के लिए है जब लाभार्थी को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही हो।

योजना में शामिल होते समय आयु	योगदान का वर्ष (60वर्ष–वास्तविक आयु)	सांकेतिक मासिक योगदान (रुपये में)	लाभार्थी को मासिक पेंशन (रुपये में)	लाभार्थी द्वारा नामांकित व्यक्ति को समस्त सांकेतिक वापसी (रुपये में)
18	42	84	2000	3.4 लाख
20	40	100	2000	3.4 लाख
25	35	151	2000	3.4 लाख
30	30	231	2000	3.4 लाख
35	25	362	2000	3.4 लाख
40	20	582	2000	3.4 लाख

साभारः प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

यह एक जीवन बीमा से संबंधित योजना है। यह योजना 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के उन नागरिकों के लिए है जिनके पास बैंक खाता है। जो लोग इस योजना को 50 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व अपनाते हैं उन्हें 55 वर्ष तक जोखिम कवर मिलता है बशर्ते इसकी निर्भरता इस पर है कि बीमा का प्रीमियम कितना है।

सामान्यतः इस योजना में प्राकृतिक और दुर्घटना दोनों तरह की मौत होने पर आश्रितों को दो लाख रुपये की बीमा राशि देने का प्रावधान है। इसका सालाना प्रीमियम 330 रुपये है जो एकमुश्त स्वयं लाभार्थी के खाते से कट जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जीवन बीमा निगम और दूसरी उन बीमा कंपनियों को, जो इच्छुक हैं, लगाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना

देश के नागरिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था खासकर के गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री की सर्वप्रिय जन धन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत खाता खोलने वाले 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के ग्राहकों से हर महीने एक रुपया काटा जाएगा जो स्वतः खाते से कट जाएगा। इसे बीमा स्कीम में जोड़ा जाएगा। यानी हर वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम बीमा के लिए देना होगा और इसके बदले दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी। इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और दूसरी अन्य इच्छुक कंपनियों के द्वारा किया जाएगा।

सामाजिक रूप से पिछड़े उद्यमियों के लिए मुद्रा बैंक

वित्तमंत्री ने अपने बजट में सामाजिक रूप से पिछड़े उद्यमियों के लिए मुद्रा बैंक का गठन करने की घोषणा की है। तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ शुरू होने वाले इस बैंक के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका ऋण गारंटी कोष 3000 करोड़ रुपये का होगा। यह मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पुनर्वित्त संस्थान होगा।

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना

सरकार अल्पसंख्यकों को हुनरमंद बनाने का काम जारी रखेगी, चाहे उनके पास औपचारिक स्कूल प्रमाणपत्र हो या न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए 'नई मंजिल' नाम की एकीकृत शिक्षा और आजीविका योजना शुरू की जाएगी।

प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम

इसके माध्यम से सभी छात्रवृत्तियों और साथ ही शिक्षा ऋण स्कीमों के आद्योपांत प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी युक्त छात्र वित्तीय सहायता प्रधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार तथा केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं)
ई–मेल : mayank5782@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

बजट : 2015–16

किसानों को सस्ता ऋण और ऋण चुकाने में भी मदद

—शिशिर सिन्हा

किसान आखिरकार दिवालिया क्यों हो जाता है, बदहाली क्यों आ जाती है या फिर गरीबी के दुष्चक्र में कैसे फंस जाता है? इसका कारण साफ है। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, बेहतर बीजों का अभाव, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल नहीं होना, पैदावार के समुचित विपणन में परेशानी जैसे कारण किसानों की बिगड़ती स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या ऐसे में किसानों के लिए बस रियायती शर्तों पर ज्यादा ऋण का इंतजाम कर देना काफी होगा? किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को किन-किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा, इस पर इस लेख में चर्चा की गई है।

सामान्य तौर पर हम दाता से स्वयं और अपने परिवार के सुखी होने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम दाता के सुखी होने की कामना करने लगे तो यह मानना स्वाभाविक है कि दाता परेशानी में है। अगर कृषि प्रधान देश माने जाने वाले भारत में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े लगातार बढ़ते रहे, किसानी से लोगों का मोहभंग होने लगे और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी घटती जाए, तो समझ लीजिए कि अन्नदाता वाकई मुसीबत में हैं।

यकीन ना हो तो संसद में सरकार के जवाब पर नजर डाल लीजिए। 27 फरवरी, 2015 को राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी कि पिछले तीन माह के दौरान दो राज्य सरकारों– महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने कृषि आपदाओं के कारण क्रमशः 337 और 02 किसानों की आत्महत्या की जानकारी दी। पूरे 2014 वर्ष की बात करें तो महाराष्ट्र में ये संख्या 986, तेलंगाना में 84, कर्नाटक में 29 (अप्रैल–दिसम्बर के आंकड़े), गुजरात में 04 (अक्टूबर तक के आंकड़े), केरल में 3 और आंध्र प्रदेश में 13 रही। आखिरकार किसान आत्महत्या क्यों करता है? इस बारे में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) ने पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, नशाखोरी/नशे की लत, बेरोजगारी, सम्पत्ति विवाद, दीवालियापन अथवा आर्थिक स्थिति में अचानक परिवर्तन, गरीबी, व्यावसायिक/कैरियर संबंधी समस्या, प्रेम प्रसंग, बांझपन/नपुंसकता, शादी टूटना/शादी न होना, दहेज विवाद, और सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट जैसे कई कारण गिनाए हैं।

केंद्र सरकार ने वित्तवर्ष 2006–07 में फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना की शुरुआत की। यह ऋण छोटी अवधि (एक वर्ष या उससे कम) के लिए दिया जाता है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार बैंकों की ओर से हर वर्ष ऋण का लक्ष्य तय करती है। किसान ज्यादा से ज्यादा तीन लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं जिस पर सालाना

ब्याज की दर 7 प्रतिशत होती है। बाद में एक और सुविधा दी गई। जो किसान समय पर ऋण चुका देते हैं, उन्हे अगला ऋण महज चार प्रतिशत ब्याज पर मिल जाता है। इस समय ऐसे कुल ऋण खातों की संख्या 5.72 करोड़ है। इसी तरह वर्ष 2014–15 के लिए बैंकों के सामने कृषि ऋण का लक्ष्य 8 लाख करोड़ रुपये का है जिसमें से 30 सितम्बर, 2014 तक 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है। अब 2015–16 में 8.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन क्या इस तरह की योजना से किसानों को वाकई में फायदा हुआ है?

27 फरवरी, 2015 को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि फसल ऋण वांछित लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहे हैं और बैंकों की कुछ शाखाओं में धन के अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था या प्रक्रिया नहीं है। यही नहीं ऋण प्रवाह बढ़ने के बावजूद, कृषि में दीर्घकालिक ऋण की हिस्सेदारी 2006–07 के 55 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 39 प्रतिशत रह गई है। सबसे ज्यादा दुखद स्थिति ये है कि तमाम सहूलियतों के बावजूद किसान सूदखोर महाजनों के चंगुल से निकल नहीं पाया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 70वें दौर के आंकड़ों के मुताबिक संस्थागत ऋण में प्रवाह बढ़ने के बावजूद किसान अपने कुल ऋण का करीब 40 प्रतिशत अनौपचारिक स्रोत जैसे सूदखोर महाजन से लेता है।

जाहिर है कि रियायती ऋण की व्यवस्था शुरु होने के नौ वर्षों के दौरान ज्यादा जोर लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा करने और उसे हासिल करने पर रहा। लेकिन नई सरकार ने अपनी रणनीति बदली। मकसद है कि किसानों को केवल ऋण लेने में ही सहूलियत नहीं मिले, बल्कि ऋण चुकाने में भी उसे सहूलियत हो। इस कड़ी में पहली कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को संगठित वित्तीय व्यवस्था के दायरे में लाया जाए। यहां प्रधानमंत्री जन–धन योजना मददगार बनी। वैसे तो वित्तीय समावेशन की पुरानी योजना के तहत भी ग्रामीण इलाकों पर जोर था, लेकिन वहां हरेक वंचित परिवार के बजाए 2000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों पर ध्यान दिया गया। नतीजा, किसानों को वो फायदा नहीं मिल सका। लेकिन प्रधानमंत्री जन–धन योजना में बैंकिंग सुविधा से वंचित एक–एक परिवार पर ध्यान देने का फायदा ये हुआ कि 28 फरवरी, 2015 तक कुल 13.68 करोड़ बैंक खाते खुले, उसमें करीब 60 प्रतिशत यानी 8.16 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हैं, यानी भारी तादाद में किसान संगठित वित्तीय व्यवस्था में आ सके। ऐसे में ऊंचे लक्ष्य का फायदा लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान होगा, जिसके बारे में आर्थिक समीक्षा में चिंता व्यक्त की गई।

किसानों को ऋण चुकाने में तभी सहूलियत होगी जब न केवल पैदावार बेहतर हो, बल्कि उसे सही समय पर वाजिब कीमत पर बेचने में भी मदद मिले। पहले बात पैदावार बेहतर करने की। इसके लिए जरूरी है कि उन्नत बीज के साथ मिट्टी की सेहत का ध्यान रखा जाए, साथ ही मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था हो। इसी के मद्देनजर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2015–16 के अपने बजट भाषण में मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए कृषि मंत्रालय की परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए पैसा मुहैया कराने का ऐलान किया। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में ही मिट्टी की सेहत के लिए योजना की शुरुआत की। इस बारे में प्रधानमंत्री ने 11 जून, 2014 को अपनी सोच कुछ इस तरह जाहिर की थीः

"हमारी इतनी कृषि यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत रिसर्च हो रही हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य रहा है कि जो लैब में है, वह लैण्ड पर नहीं है। लैब से लैण्ड तक की यात्रा में जब तक हम उस पर बल नहीं देंगे, आज कृषि को परंपरागत कृषि से बाहर लाकर आधुनिक कृषि की ओर ले जाने की आवश्यकता है। गुजरात ने एक छोटा–सा प्रयोग किया था–सॉयल हेल्थ कार्ड। हमारे देश में मनुष्य के पास भी अभी हेल्थ कार्ड नहीं हैं। लेकिन गुजरात में हमने एक इनीशिएटिव लिया था। उसकी ज़मीन की तबीयत का उसके पास कार्ड रहे। उसके कारण से पता चला कि उसकी जमीन जिस क्रॉप के लिए उपयोगी नहीं है, वह उसी फसल के लिए खर्चा कर रहा था। जिस फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है,

उतनी मात्रा में वह फर्टिलाइजर डालता था। जिन दवाइयों की कतई जरूरत नहीं थी, वह दवाइयां लगाता था। बेकार ही साल भर में 50 हजार रुपये या लाख रुपये यूं ही फेंक देता था। लेकिन सॉयल हेल्थ कार्ड के कारण उसको समझ आई कि उसकी कृषि को कैसे लिया जाए। क्या हम हिन्दुस्तान के हर किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड देने का अभियान पूर्ण नहीं कर सकते? हम इसको कर सकते हैं। सॉयल टैस्टिंग के लिए भी हम अध्ययन के साथ कमाई का एक नया आयाम ले सकते हैं।"

मिट्टी की सेहत का अंदाजा मिलने के बाद जो भी फसल लगायी जाए, वो तभी बेहतर होगी, जब उसके लिए सिंचाई का समुचित इंतजाम हो। इस बारे में वित्तमंत्री ने 'प्रति बूंद, अधिक फसल का नारा देते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के साथ सूक्ष्म सिंचाई और जलसंभर विकास के लिए पांच हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का प्रावधान किया है।

मिट्टी और पानी के बाद खाद की बात तो होगी ही। हालांकि सरकार यह कोशिश कर रही है कि किसान बड़े पैमाने पर यूरिया का इस्तेमाल नहीं करे। लेकिन चूंकि तमाम खादों में केवल यूरिया ही ऐसा है जिसकी खुदरा कीमत सरकार तय करती है और पिछले कई वर्षों से अभी भी यह 5,360 रुपये प्रति टन पर टिकी है जबकि लागत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लागत और खुदरा कीमत के बीच का अंतर सब्सिडी के तौर पर सरकार कम्पनियों को मुहैया कराती है। दूसरी ओर बाकी खाद में पौष्टिक तत्वों के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, जबकि खुदरा कीमत तय करने के लिए कम्पनियों को आजादी मिली है। बहरहाल, सरकार ने साफ कर दिया है कि यूरिया की कीमत तुरंत नहीं बढ़ने वाली। इसे ध्यान में रखते हुए यूरिया समेत तमाम खाद के लिए 2015–16 में 72,900 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी का इंतजाम किया गया है जो 2014–15 के संशोधित अनुमान से करीब दो हजार करोड़ रुपये ज्यादा है।

पैदावार पूरी हो जाने के बाद किसान की चिंता होती है कि फसल न केवल सही समय पर बिक जाए, बल्कि उसके लिए उचित कीमत भी मिले। इस संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था तो वर्षों से है और वर्ष–दर–वर्ष उसमें बढ़ोतरी की जाती रही है। लेकिन आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सरकारी खरीद ही होती है, आम व्यापारी अपनी ही शर्तों पर किसानों को मजबूर करते हैं। इस बारे में वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा–

"ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उपजों के लिए वाजिब दाम प्राप्त होना आवश्यक है। हमें सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की क्षमता में सुधार लाने तथा मूल्यवर्धन और कृषि से होने वाली आय में वृद्धि करने तथा कृषि उत्पादों के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।"

- सभी किसानों को मिलेंगे मृदा हेल्थ कार्ड।
- परम्परागत कृषि विकास योजना को पूर्ण सहायता।
- सूक्ष्म सिंचाई, जलसंभर विकास और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता हेतु 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन।
- 2015–16 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 8.5 लाख करोड़ रुपये।
- अलग कोषों के जरिए एक लाख करोड़ रुपये की अलग से उपलब्धता।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने का प्रस्ताव।
- किसानों को मदद, मूल्यवृद्धि पर लगाम में मदद।

कृषक परिवारों की स्थिति के प्रमुख संकेतक

स्रोतः राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन

कृषक परिवारों की संख्या

- जुलाई 2012–जून 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में अनुमानित कुल 9.02 करोड़ कृषक परिवार, कुल अनुमानित ग्रामीण परिवारों का लगभग 57.8 प्रतिशत।
- उत्तर प्रदेश में अनुमानित 1.80 करोड़ कृषक परिवार, देश में कृषक परिवारों का 20 प्रतिशत।
- कुल ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों का सबसे ज्यादा प्रतिशत (78.4), राजस्थान में। सबसे कम (27.3 प्रतिशत) केरल में।
- देश में कुल अनुमानित कृषक परिवारों में लगभग 45 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के, लगभग 16 प्रतिशत कृषक परिवार अनुसूचित जाति के तथा 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के।

इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि बाजार की अवधारणा विकसित करने की बात कही गयी है। यहां वित्तमंत्री कहते हैं–

"हालांकि, किसान अब स्थानीय व्यापारी के शिकंजे में नहीं हैं परन्तु उसके उत्पाद को अभी भी सर्वोत्तम राष्ट्रीय कीमत नहीं मिलती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्रीय कृषि बाजार सृजित करें जिससे मूल्य वृद्धि को कम करने के अनुषंगी लाभ होंगे। मैं, इस वर्ष एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन हेतु नीति में राज्यों के साथ कार्य करने का इच्छुक हूं।"

अल्पकालिक कृषि कर्ज (करोड़ रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2010–11	3,75,000	4,68,291
2011–12	475,000	5,11,029
2012–13	5,75,000	6,07,375
2013–14	7,00,000	7,30,765.61
2001–15	8,00,000	3,70,828.60
2015–16	8,50,000	

30 सितम्बर, 2014 तक के आंकड़े

स्रोतः बजट दस्तावेज

यहां ध्यान देने की बात ये है कि संविधान के तहत 'कृषि राज्य' का विषय है। साथ ही कृषि उत्पादों के विपणन के लिए कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। वैसे तो इस कानून को बनाए जाने का मकसद किसानों को अनाज बेचने में सुविधा देना था, लेकिन एक तय मंडी के द्वारा अनाज बेचने की बाध्यता से व्यापारियों पर मनमर्जी तरीके से कीमत तय करने और किसानों का शोषण करने के आरोप लगते रहे हैं। इसके मद्देनजर वर्षों से केंद्र सरकार इस कानून में बदलाव लाने के लिए राज्य सरकारों से अपील करती रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अलग बाजार व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि आम लोगों के लिए अनाज, फल और सब्जियों की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

इन सभी उपायों के जरिए सरकार चाहती है कि किसान का तो भला हो ही, किसानी भी खूब पनपे। किसान की गाड़ी तभी चल सकती है, जब किसानी फायदेमंद रहे। किसान ऋण चुकाने की स्थिति में तभी होगा, जब किसानी से उसे समुचित कमाई हो। आज हालात ये हैं कि 60 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। वो तो भला हो सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन के तौर–तरीको में बदलाव का जिसकी वजह से कृषि करीब छठे हिस्से तक पहुंच पाई है।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय आय की नई श्रृंखला के अनुसार, 2011–12 के मूल्यों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया, जबकि पिछली श्रृंखला में ये 15 प्रतिशत के ऊपर नहीं जाने का अनुमान था। कृषि की विकास दर की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017) के बीच 4 प्रतिशत का लक्ष्य है जिसके मुकाबले 2012–13 में 1.2 प्रतिशत, 2013–14 में 3.7 प्रतिशत और 2014–15 में 1.1 प्रतिशत की दर से विकास का अनुमान है।

विकास के इन आंकड़ों के बीच आत्महत्या के बढ़ते चलन के साथ कुछ और तथ्य ऐसे भी सामने आए हैं जिसने चौंकाया ही नहीं, बल्कि बेहद गंभीर स्थिति को ओर इशारा भी कर दिया है। इनमें से दो का खासतौर पर उल्लेख करना जरूरी होगा। एक भारतीय किसानों पर अध्ययन को लेकर सीएसडीएस की रिपोर्ट और दूसरा भारत में कृषक परिवारों की स्थिति के मुख्य संकेतक पर एनएसएसओ की रिपोर्ट।

पहली रिपोर्ट के मुताबिक, 72 प्रतिशत किसानों ने किसानी पसंद करने की बात कही, जबकि 22 प्रतिशत का जवाब नहीं में था। लेकिन ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि कृषक परिवार के युवाओं से जब किसानी जारी रखने की बात पूछी गई तो केवल 24 प्रतिशत ने 'हां' में जवाब दिया जबकि 76 प्रतिशत ने कहा कि वो किसानी के अलावा दूसरा काम करना बेहतर समझेंगे। ध्यान देने की बात ये है कि देश की कुल आबादी का 65 प्रतिशत, 35 वर्ष से कम उम्र का है। इस रिपोर्ट के नतीजे 18 राज्यों के 137 जिलों में 274 गांवों के पांच हजार से भी ज्यादा परिवारों से बातचीत के आधार पर निकाले गए।

दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक देश में आधे से भी ज्यादा कृषक परिवार ऋणग्रस्त हैं। राज्यवार बात करें तो आंध्र प्रदेश 92.9 प्रतिशत परिवारों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 89.1 प्रतिशत के साथ दूसरे और तमिलनाडु 82.5 प्रतिशत कृषक परिवारों के साथ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में ये भी जानकारी मिली कि लगभग 60 प्रतिशत ऋण ही संस्थागत थे। संस्थागत से यहां मतलब सरकार, सहकारी समिति और बैंकों से लिया गया ऋण है। बाकी 40 प्रतिशत सूदखोर, महाजन जैसी व्यवस्था से लिए गए जिनसे किसानों की परेशानी बढ़ी। गौरतलब ये है कि ये नतीजे देश के 4,529 गांवों में जनवरी से दिसम्बर, 2013 के बीच चयनित परिवारों के बीच सर्वेक्षण के आधार पर निकाले गए।

किसानों की परेशानी ये भी रही है कि राजनीतिक बहस में उन्हें जगह तो मिलती है, लेकिन उनके लिए समस्या का समाधान भी बहस में ही उलझकर रह जाता है। नतीजा किसानों की आत्महत्या और किसानी से मोहभंग जैसे चलन जोर पकड़ने लगते हैं। फिलहाल उम्मीद है कि नई सरकार की सोच और नए बजट में शामिल किए गए एक संपूर्ण पैकेज से हालात बदलेंगे। महज ऋण के लक्ष्य बढ़ाए जाने की घोषणा नहीं होगी, बल्कि ऋण चुकाने का पूरा इंतजाम होगा। ऐसा हुआ, तभी जाकर अन्नदाता यानी किसान के सुखी होने की कामना सच्चाई में बदल सकेगी।

**(लेखक 'द हिंदू' बिजनेस लाइन में डिप्टी एडिटर के पद पर कार्यरत है।
और आर्थिक मुद्दों पर दो दशकों से लेखन)
ई–मेलः hblshishir@gmail.com**

तकनीकी उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाएगा यह बजट

—बालेन्दु दाधीच

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणाएं आम बजट में नहीं की गई हैं, जैसे करों में बड़ी राहत या किसी खास किस्म को प्रोत्साहन दिया जाना। लेकिन नए उपक्रमों (स्टार्ट-अप्स) को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के कोष की घोषणा करके सरकार ने इस उद्योग में नई जान फूंकने की कोशिश जरूर की है। कई अन्य बजट प्रावधान भी किसी न किसी रूप में आईटी उद्योग की मदद करेंगे।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली की ओर से पेश किए गए बजट का केंद्रीय थीम विकास को गति देना है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी उन्होंने अपने बजट प्रावधानों के जरिए यही संदेश दिया है—कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं परोक्ष ढंग से।

भारत में जिस तरह ई–कॉमर्स कंपनियों और उद्यमशीलता का दौर चला है, वह किसी सुखद आश्चर्य की तरह है। इंटरनेट को माध्यम बनाकर सैंकड़ों छोटी कंपनियों ने बड़ा नाम कमाया है और रातोंरात कुछ करोड़ रुपये से कुछ हजार करोड़ रुपये तक का रास्ता तय कर लिया है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, यात्रा, ओएलएक्स, क्विकर, बुक माइ शो, रेड बस, नौकरी, गाना जैसी दर्जनों कंपनियों ने अपनी कामयाबी से प्रभावित किया है। जाहिर है कि देश में उद्यमशीलता की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है और बाजार की स्थितियां भी उसके अनुकूल हैं। इस घटनाक्रम को केंद्र सरकार बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रही है क्योंकि ये छोटे उपक्रम देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं जो आर्थिक विकास के हमारे लक्ष्य में मददगार सिद्ध होगा। स्टार्ट–अप कम निवेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने में मदद कर सकते हैं, उत्पादों तथा सेवाओं का उपयोगी वितरण नेटवर्क तैयार कर सकते हैं और निर्यात के लक्ष्यों में भी कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं। उन्हें बढ़ावा दिए

जाने की जरूरत है और श्री जेटली ने इस तथ्य को नजरंदाज नहीं किया है।

हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणाएं आम बजट में नहीं की गई हैं, जैसे करों में बड़ी राहत या किसी खास किस्म का प्रोत्साहन दिया जाना। लेकिन नए उपक्रमों (स्टार्ट–अप्स) को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के कोष की घोषणा करके उन्होंने इस उद्योग में नई जान फूंकने की कोशिश जरूर की है। कई अन्य बजट प्रावधान भी किसी न किसी रूप में आईटी उद्योग की मदद करेंगे।

आम बजट में नए उद्यमों को शुरुआती धनराशि मुहैया कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर वित्तमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक अहम जरूरत को पूरा किया है। सॉफ्टवेयर कंपनियों के संगठन नासकॉम के अनुसार इस समय देश में 3100 स्टार्ट–अप कंपनियां सक्रिय हैं और इस सूची में हर साल करीब 800 नई कंपनियां जुड़ जाती हैं। इन्हें अब तक देश–विदेश से करीब 2.3 अरब डालर (करीब 14,200 करोड़ रुपये) का निवेश प्राप्त हो चुका है। इसे देखते हुए जाहिर है, केंद्र की ओर से शुरू किए गए कोष की राशि बहुत अधिक नहीं है लेकिन श्री जेटली ने सही दिशा में, सकारात्मक शुरुआती कदम उठाया है। आने वाले वर्षों में यह राशि बढ़ भी सकती है और इससे औद्योगिक समूह तथा वित्तीय संस्थान भी स्टार्ट–अप कंपनियों को सहयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। टाटा समूह और इन्फोसिस पहले ही कुछ ई–कॉमर्स कंपनियों में निवेश की पहल कर चुके हैं। याद रहे, श्री जेटली ने अपने जुलाई 2014 के बजट भाषण में भी स्टार्ट–अप कंपनियों को अंशधारिता, आसान शर्तों वाले ऋणों और जोखिम पूंजी के तौर पर मदद देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराने की घोषणा की थी।

वित्तमंत्री ऐसी कंपनियों के जरिए करीब एक लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मूलभूत लक्ष्य है–भारतीय युवाओं को रोजगार तलाशने वालों की बजाए रोजगार देने वालों में तब्दील करना। आमतौर पर छोटी स्टार्ट–अप कंपनियां युवाओं द्वारा खड़ी की जाती हैं जिन्हें प्रायः उद्यमशीलता का पहले से कोई अनुभव नहीं होता। अगर अपना कारोबार संभालने के लिए जरूरी प्रशिक्षण, अनुभवी व्यावसायियों का मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग मिल जाए तो युवा उद्यमियों की कामयाबी के आसार बेहतर हो सकते हैं।

करीब 150 अरब डॉलर का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में खासी अहमियत रखता है। सॉफ्टवेयर, परामर्श सेवाएं और आउटसोर्सिंग इसके अहम अवयव हैं। धीरे–धीरे हार्डवेयर विनिर्माण का क्षेत्र भी उभर रहा है। इस साल के आम बजट में वित्तमंत्री ने आईटी उत्पादों पर चले आ रहे विशेष अतिरिक्त शुल्क को हटाने की घोषणा की है जो हार्डवेयर विनिर्माताओं को खासी राहत देगा। हालांकि पर्सनल कंप्यूटरों (पीसी) के विनिर्माण को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है। कलपुर्जों के आयात से सीमा–शुल्क को हटाया जाना भी एक अच्छा कदम है। हालांकि 'मेक इन इंडिया' के दौर में पीसी विनिर्माताओं के लिए किसी खास प्रोत्साहन या राहत की घोषणा न करना थोड़ा निराशाजनक माना जा रहा है।

> बजट प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक स्वरोजगार और प्रतिभा प्रयोग तंत्र स्थापित करने जा रही है। इस साल के बजट में तकनीकी स्टार्ट–अप कंपनियों की रॉयल्टी और अन्य संबंधित करों को 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। वित्तमंत्री का संदेश स्पष्ट है– सरकार देश में उद्यमशीलता के अनुकूल स्थितियां पैदा करना चाहती है।

विदहोल्डिंग टैक्स घटाए जाने से आईटी उद्योग पर अच्छा असर पड़ेगा जो रॉयल्टी पर कर को 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी तक ले आएगा। इसी तरह कंपनी कर में होने वाली कटौतियों का लाभ दूसरे उद्योगों के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी को भी मिलेगा। सरकार अगले चार साल में कंपनी कर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी पर लाने जा रही है जो सकारात्मक कारोबारी माहौल विकसित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुकूल है। यही बात शोध और विकास (आर एंड डी) और नवाचार संबंधी निवेश पर कर को घटाकर 10 फीसदी तक ले आए जाने पर भी लागू होती है जो नई तकनीकों के हस्तांतरण के साथ–साथ नवोन्मेष को बढ़ावा देगा। गार को दो साल के लिए टाले जाने और घरेलू हस्तांतरण मूल्य की सीमा को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये तक ले जाने का ऐलान भी दूसरे उद्योगों के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के पक्ष में है।

हालांकि आईटी उद्योग की कुछ अन्य मांगों को वित्तमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया है, जैसे एंजेल फंडिंग (स्टार्ट–अप में बाहरी निवेश) को करमुक्त करना और अनेक उत्पादों पर दोहरे कराधान की समस्या से छुटकारा दिलाना। कुछ आईटी उत्पादों पर सेवा कर और बिक्री कर दोनों लागू होते हैं और देश के कर ढांचे को सरल तथा कारपोरेट माहौल के अनुकूल बनाने के सरकार के इरादे के मद्देनजर इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मोटे तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने बजट प्रावधानों को सही दिशा में उठाए गए मजबूत कदम के तौर पर देखा है। हालांकि भविष्य में उसे वित्तमंत्री से कुछ और ठोस रियायतें पाने की अपेक्षा है।

(लेखक सूचना तकनीक के विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेलः balendudadhich@gmail.com

ALS सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन हेतु हन्दी माध्यम को समर्पित संस्थान

ISGS Indian School of General Studies

INDIAN SCHOOL OF GENERAL STUDIES

IAS 2016

The Best Programme for ***Full IAS Preparation***

IAS EXTENSIVE — Prelims / Main / Interview

GS + CSAT + OPTIONAL + ESSAY + INTERVIEW

बैच प्रारंभ 19 मई एवं जून 10

Time: 3:00pm   Time: 6:00pm

नामांकन प्रारंभ: अप्रैल 14

Alternative Learning Systems ALS 22 YEARS

Take Admission before **MAY 10** *& Get special concession of* **Rs.45,000/-** *for IAS Extensive Course*

Get Special Concession *of*

Rs. 45,000/- *in Package Programme* IAS Complete Preparation (GS+CSAT+ Optional+Essay)

Rs. 32,000/- *in General Studies & CSAT Programme*

SPECIAL FEE *for* **GS BATCH** Concessional Fee

GS Fee Rs. 81,000/-, Concession 32,000/-	Rs. 49,000/-
GS+Optional Fee Rs. 1,22,000/- Concession Rs. 45,000/-	Rs. 77,000/-

Last date for Admission **MAY 15**

हिन्दी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट

विगत वर्षों में हिन्दी माध्यम से कई अभ्यर्थियों का चयन। साथ ही ALS संस्थान से अब तक 1808+ सफल अभ्यर्थियों का चयन, वर्ष 2014 में कुल चयन = 215+, अब तक 2 IAS TOPPERS का चयन।

Jai Prakash Maurya	Manoj Jain	Neelima	Manish Kumar	Deepa Agrawal	Kana Ram
AIR 9 (2010)	AIR 15 (2005)	AIR 23 (2008)	AIR 40 (2013)	AIR 52 (2013)	AIR 54 (2013)

निबंध essay writing

The Best Ever ALS Essay Programme for हिन्दी माध्यम Aspirants

Batch Begins Mar 31

250 Marks, 10 Sessions, 03 Full Tests

31 March to 09 April, 6:00PM

The Best Ever Specialists in Core Areas

शशांक एटम, हेमन्त झा, आर.सी. सिन्हा, सचिन अरोड़ा, शरद त्रिपाठी एवं अन्य विशेषज्ञ

Programme Director: **Manoj Kumar Singh**

Fee: Rs. 900/- (Valid till 28 March)

ALS Old Students: 500/-

essay test series

Three 3-hour tests starting 07th April, 1 test every month

प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में नया बैच प्रारंभ

IAS सामान्य अध्ययन "तैयारी कैसे करें"

3 दिवसीय IAS कार्यशाला

अब आपके शहर में

पहली बार शीघ्र ही आयोजित। यह कार्यशाला अप्रैल-मई-जून के महीने में आयोजित की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन हेतु SMS करें- 9891990011, 9999344944

- पटना
- जयपुर
- लखनऊ
- इलाहाबाद
- इंदौर
- भोपाल
- पुणे
- पानीपत
- अजमेर
- जोधपुर

द्वारा

MANOJ KUMAR SINGH & ALS TEAM

Managing Director: ALS, ISGS, Competition Wizard

IAS 2015

प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम-2015

30 Tests

16 Tests GS

14 Tests CSAT

Batch Begins **April 05**

Test Timing: 11:30am - 01:30pm

Explanation: 02:00pm - 04:30pm

फीस केवल Rs. 3,500/-

ALS के पुराने विद्यार्थियों हेतु केवल 2,000/- रु.

9999343999
9891990011
9999344944

ALS Alternative Learning Systems

Alternative Learning Systems (P) Ltd.

Corporate Office: ALS, B-19, ALS House, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-110009.

South Delhi Centre: 62/4, Ber Sarai, Delhi-110016

Visit us at www.iaslas.com

Be in touch...

Manoj K Singh

Managing Director, ALS

alsiasindia@gmail.com

KH-385/2014

बजट : 2015–16

बिजली और कुटीर उद्योगों की मजबूती पर बल

— देवेन्द्र उपाध्याय

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के अपने आम बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की फंडिंग हेतु कदम उठाने और इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने का वायदा किया है। बजट में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों समेत सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए देश को ऊर्जायुक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। बजट में मझोले, लघु और कुटीर उद्योगों तथा व्यापारियों के लिए वित्तीय उपलब्धता सुधारने और कारोबार आसान बनाने के उपाय किए गए हैं।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीपीपी मॉडल की समीक्षा की जाएगी और उसमें जान फूंकी जाएगी। बजट में 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जरूरत के मुताबिक हजारों करोड़ रुपये जुटाने की भी व्यवस्था की गई है। देश की एक लाख 78 हजार बस्तियों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसमें डेढ़ लाख करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है।

वर्ष 2015–16 के बजट प्रस्तावों में सामाजिक आधारभूत ढांचे पर फोकस किया गया है। इसमें अनेक नए सामाजिक सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है, जिसके दूरगामी परिणाम निकलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। बजट के अनुसार सड़क, रेल, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा, वहीं सामाजिक ढांचे की मजबूती के लिए हर घर को साफ पीने का पानी तथा 2022 तक शौचालय उपलब्ध कराने, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण से देश के ग्रामीण क्षेत्र की जिन्दगी को बदल पाना सम्भव है।

बजट प्रस्तावों में सड़कों और रेलवे के लिए आउट–ले में वृद्धि की गई है। सड़कों के लिए 14031 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जबकि रेलवे के बजटीय समर्थन में 10050 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। बजट प्रस्तावों में सड़कें बढ़ाने के कार्य को तेज करने तथा उसका विस्तार करने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत अभी एक लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है और एक लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए नई परियोजनाएं तैयार होंगी। इतनी बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण होने से इस्पात एवं सीमेंट तथा अन्य उत्पादों की मांग एवं खपत में भी बढ़ोतरी होगी। वित्तमंत्री ने अनेक ढांचागत परियोजनाओं के लिए टैक्स–फ्री बांड लाने का वायदा भी किया है। उन्होंने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात भी अपने बजट भाषण में की है जिसका वार्षिक प्रवाह 20 हजार करोड़ रुपये का होगा तथा सरकारी बैंकों का पूंजीगत व्यय 80444 करोड़ से बढ़ाकर 317889 करोड़ रुपये किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जोखिम के रिबैलेंसिंग का है। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकार को जोखिम का बड़ा हिस्सा उठाना होगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बीते एक दशक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास मोर्चे पर चूक हुई है। हमारी अवसंरचना हमारी विकास महत्वाकांक्षा के अनुरूप नहीं है। इसके लिए तत्काल सार्वजनिक निवेश को बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने इससे सम्बन्धित अनेक विशिष्ट प्रस्ताव किए हैं। इनमें सड़क और अन्य अवसंरचना में निवेश का वित्तपोषण करने के लिए चार रुपये प्रति लीटर तक लगने वाले वर्तमान उत्पाद शुल्क को सड़क उपकर में परिवर्तित करना शामिल है। इन क्षेत्रों के लिए इस उपाय के जरिए 40 हजार करोड़ रुपये की राशि जुटायी जाएगी। पेट्रोल तथा हाईस्पीड डीजल पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क की दरें दो रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर आठ रुपये प्रति लीटर तक की जा सकती हैं। इससे मिलने वाली धनराशि का उपयोग बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास पर किया जा सकता है।

बिजली उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य

बजट में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों समेत सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए देश को ऊर्जायुक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें सन् 2020 तक ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा सहित शेष 20 हजार गांवों का विद्युतीकरण करने की घोषणा की गई है। वित्तमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से पांच अति वृहद (मेगा) ताप बिजली परियोजनाएं लगाने की घोषणा की है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को सन् 2022 तक बढ़ाकर 1.75 लाख मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर ऊर्जा का योगदान एक लाख मेगावाट, पवन ऊर्जा का योगदान 60 हजार मेगावाट, बायोमास ऊर्जा का 10 हजार मेगावाट तथा लघु पनबिजली का योगदान 5 हजार मेगावाट होगा। अभी कुल बिजली में अक्षय ऊर्जा का योगदान 6.5 प्रतिशत है, जिसे आगामी तीन वर्ष में बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। परियोजनाओं को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अध्यादेश द्वारा कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं।

मझोले, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

बजट में मझोले, लघु और कुटीर उद्योगों तथा व्यापारियों के लिए वित्तीय उपलब्धता सुधारने और कारोबार आसान बनाने के उपाय किए गए हैं। बजट के अनुसार देश में करीब 5.77 करोड़ छोटे उद्यम तथा व्यापार हैं जिनमें अधिकतर निजी स्वामित्व वाले हैं। इनमें बडी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमी तथा व्यापारी शामिल हैं। इनके लिए बजट में मुद्रा बैंक बनाने और उसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये की निधि तथा 3 हजार करोड़ रुपये की गारंटी राशि की घोषणा करके इस क्षेत्र को मजबूती देने का प्रयास किया गया है। इससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कर्ज दिया जाएगा।

सीमांत और मझोले किसानों के लिए बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रस्ताव किया गया

है। इसी तरह बुनियादी ढांचे और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में निवेश आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी ढांचा निधि स्थापित करने का संकल्प बजट में किया गया है।

वित्तवर्ष 2015–16 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 8.5 लाख करोड़ रुपये घोषित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि ऋण हमारे मेहनती किसानों को सहारा देते हैं। उन्हें विश्वास है कि बैंक इस लक्ष्य को पार कर लेंगे। किसानों को प्रभावी व अड़चन रहित कृषि ऋण के जरिए ग्रामीण संरचना विकास कोष में 25 हजार करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण कोष के लिए 15 हजार करोड़ रुपये, सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त कोष के लिए 45 हजार करोड़ रुपये, लघु अवधि के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्त कोष के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई जल वितरण कार्यक्रमों एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई के लिए 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

देश में कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास के लिए जल्दी ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत सरकार कुछ मंत्रालयों के साथ पहल करेगी। मिशन से 31 क्षेत्रों में कौशल विकास परिषद की मानक प्रक्रियाओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

निवेश बढ़ाने के उपाय

रीयल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट्स) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) के प्रायोजकों के लिए पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है। वैकल्पिक निवेश कोष (ए.आई.एफ.) में विदेशी निवेश को मंजूरी देने का प्रस्ताव किया गया है। इस बारे में वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे निवेशों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे विभिन्न खंडों को खत्म करेगी ताकि विदेशी निवेशकों के लिए ए.आई.एफ. में निवेश आसान हो।

मनरेगा योजना का बजट आवंटन बढ़ा

मनरेगा योजना के लिए वर्ष 2015–16 हेतु 34699 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2014–15 की तुलना में करीब 12 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में कुल आबंटन में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जोकि 71695.08 करोड़ रुपये है। इसमें रोजगार सृजन, आवास, कौशल विकास तथा ग्रामीण सड़क सम्पर्क पर विशेष जोर दिया गया है।

शिक्षा और कौशल विकास

बजट में शिक्षित और कौशल में दक्ष वर्कफोर्स तैयार करने के लिए 'स्किल इंडिया' अवधारणा के अंतर्गत शिक्षा एवं रोजगार को एक–दूसरे से जोड़ने की रूपरेखा पेश की गई जो 25 वर्ष से कम उम्र की 54 प्रतिशत आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। राष्ट्रीय कौशल मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रावधान होंगे। ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रहने वाले छात्रों की आर्थिक मदद हेतु आईटी आधारित वित्तीय सहायता प्राधिकरण शुरू करने की बात भी बजट में की गई है जो एक ओर छात्रों की दी जाने वाली छात्रवृत्तियों को देखेगी वहीं जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही कई राज्यों में प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा भी की गई है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है।)
ई–मेल : devendra.khumar@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की बयार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

गांवों के सर्वांगीण विकास पर ज़ोर

—सबिता कुमारी

गांवों को संवारने के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण ढांचागत विकास निधि गठित की जाएगी। 'सभी को आवास' देने की योजना के तहत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने आम बजट में गांवों की सेहत व सूरत, दशा और दिशा बदलने की घोषणा की है। बजट में हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ सबको मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा व प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के पहले पूर्ण आम बजट के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में नये अध्याय की शुरुआत की है। वित्तमंत्री ने अर्थव्यवस्था के सदंर्भ में सरकार के चिंतन–मनन की झलक दे ही दी थी। आम बजट इस सर्वेक्षण के ही विस्तारित रूप में सामने आया है। उनके बजट में जिस तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और कृषि के परिदृश्य में सुधार के साथ–साथ सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने पर जोर दिया गया उससे यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार अगले पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करना चाहती है। वित्तमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और जो इस काले कारोबार में संलिप्त हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय सुधारों की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ने के संकेत दिए, जो जरूरी थे। सरकार ने देश के विशाल मध्य वर्ग का भी पूरा ध्यान रखा है। भले ही आयकर के ढांचे में कोई बदलाव नही किया गया हो, परन्तु चिकित्सा और शिक्षा पर होने वाले व्यय पर छूट देकर मध्य वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है।

सामाजिक विकास हेतु बजट

ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाकर हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। देश में अभी भी 1.78 लाख बस्तियां सड़कों से नहीं जोड़ी जा सकी हैं। वित्तमंत्री ने इन्हें जोड़ने के लिए एक लाख किमी. नई सड़कें बनाने का प्रावधान बजट में किया है। सड़कों को बनाने का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक 'सबको आवास' देने का सरकार का वादा पूरा किया जाएगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र में दो करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में चार करोड़ आवास की जरूरत है। मकानों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव मदद मुहैया कराएगी। वित्तमंत्री ने जोर देकर कहा कि बनाए जाने वाले इन घरों को पेयजल और शौचालय से लैस किया जाएगा। सभी घरों में 24 घंटे की आपूर्ति के लिए बिजली के कनेक्शन होंगे। ऐसे सभी घरों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत छह करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे।

प्रत्येक परिवार की आजीविका के लिए कम से कम एक सदस्य को रोजगार योग्य बनाया जाएगा, ताकि उस परिवार का गुजर–बसर ठीक से हो सके। प्रत्येक परिवार की सेहत के लिए चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। प्रत्येक बच्चे को अधिकतम पांच किमी. के दायरे में माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होगा। गांव की ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण ढांचागत विकास निधि का गठन किया जाएगा।

'मनरेगा' के लिए बजट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकेतों के बाद वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने मनरेगा पर खासा ध्यान रखा है। बजट आवंटन में कटौती की आशंकाओं के बीच मनरेगा को सरकार का जबर्दस्त समर्थन मिला है। उसके आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि अब कुछ ठीक रहा तो उसके मद में पांच हजार करोड़ रुपये और जोड़ दिया जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 34,699 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगारपरक इस योजना को चालू रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रारम्भिक आवंटन है, जिसमें पांच हजार करोड़ रुपये की और वृद्धि की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि योजना की खामियों को दूर करते हुए इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ग्रामीण गरीब बेरोजगार न रह जाए।

बजट से लौटेंगे किसानों के दिन

घाटे की खेती को पटरी पर लाने की कोशिश में सरकार ने आम बजट में कई अहम उपायों की घोषणा की है। लागत घटाकर उपज बढ़ाने वाली खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जबकि उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करेगी।

वित्तमंत्री ने खेती के लिए मिट्टी की सेहत परखने और फसलों की सिंचाईं के लिए पानी की उपलब्धता को आम बजट में खास प्राथमिकता दी है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें माइक्रो इरीगेशन–वाटरशेड का बजट भी शामिल है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन

वित्तमंत्री ने वादा किया है कि सिंचाईं के मद में तीन हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी किया जा सकता है। सिंचाई के बावत टैक्स फ्री बांड भी जारी करने की योजना है। कृषि लागत में कटौती के बावत परम्परागत खेती यानी जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है। इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों को जैविक खेती का हब बनाया जाएगा।

किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल उपज के उचित मूल्य को लेकर है। फसल आने के समय उन्हें लागत से कम दाम पर अपनी उपज बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इसके लिए होने वाली सरकारी खरीद बहुत कम होती है। वित्तमंत्री ने किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।

किसानों को साहूकारों की सूदखोरी से बचाने के लिए सरकार ने आगामी वित्तवर्ष के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले साल के अनुसार केवल 50 हजार करोड़ ज्यादा है। खेती के बावत ही अन्य कई तरह के भी प्रावधान किए हैं, जिनमें 25 हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण बुनियादी ढांचा निधि के साथ 15 हजार करोड़ रुपये का ग्रामीण ऋण कोष और 45 हजार करोड़ का शार्ट–टर्म ऋण कोष शामिल है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के बावत 3321 करोड़ रुपये, नीली क्रांति के लिए 411 करोड़ और डेयरी विकास के लिए 481 करोड़ रुपये और कृषि उन्नति योजना के लिए 3257 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सेवा

बढ़ती महंगाई और लागत के बावजूद केन्द्र सरकार ने सेहत पर होने वाले खर्च में कटौती की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 35 हजार करोड़ रुपये के पिछले बजट में इस बार 16 प्रतिशत कटौती की गई है। हालांकि सरकार का दावा है कि वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब वह अपने खजाने की रकम सीधे राज्यों को दे रहा है। इस वजह से स्वास्थ्य योजनाओं पर कुल खर्च में कमी नहीं आएगी।

वित्तमंत्री ने अपने भाषण में जरूर कहा कि उन्होंनें 33,152 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिए हैं। मगर सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली योजना और गैर–योजना खर्च में

सिर्फ 29,653 करोड़ रुपये ही आते हैं। पिछले बजट में यह रकम 35,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी। हालांकि यह भी सच है कि इसमें से मंत्रालय सिर्फ 29,042 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाएगा मगर यह पहला अवसर नहीं है जब आवंटित रकम से कम ही खर्च होने की उम्मीद है। मुफ्त दवा वितरण जैसी स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरी योजनाएं वर्षों से धन के इंतजार में लटके होने के बावजूद इस बार बजट में स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है।

महिला सुरक्षा

सरकार ने असुरक्षा के भय में जी रही देश की आधी आबादी को एक बार फिर सुरक्षा और निश्चिंतता का अहसास कराने की कोशिश की है। बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने निर्भया फंड में 1000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई। इतना ही नहीं महिलाओं के कुल बजट में भी बढ़ोतरी की गई है।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए वचनबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा, जागरुकता और परोपकार करने वाले कार्यक्रमों की सहायता के लिए निर्भया कोष में 1000 करोड़ रुपये और दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने एक हजार करोड़ के निर्भया कोष की स्थापना की थी। मोदी सरकार ने अपने पिछले बजट में निर्भया कोष में दरिंदगी की शिकार महिलाओं को तत्काल इलाज सुनिश्चित कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की थी। इसके तहत निर्भया कोष से अस्पतालों में आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किए जाने थे। हालांकि अभी तक इस कोष का बहुत कम हिस्सा ही उपयोग किया गया है। लेकिन 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि से निश्चित ही महिला सुरक्षा कार्यक्रमों को बल मिलेगा।

रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भी अपने बजट में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है। महिला सुरक्षा की इस योजना को अमलीजामा पहनाने में रेलमंत्री की नजर भी निर्भया कोष पर है। उन्होंने कहा था कि योजना पर आने वाले खर्च का कुछ हिस्सा निर्भया कोष से लिया जाएगा।

भविष्य हेतु लाभदायक बजट

वित्तमंत्री द्वारा पेश केन्द्रीय बजट आय–व्यय के लेखे से अधिक आगे की कहानी बयां कर रहा है। गहराई में जाने पर यह राजग के सरकार में बाकी बचे दिनों का रोडमैप प्रतीत हो रहा है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था किस तरीके से स्थायित्व पूर्ण, अनुमान योग्य, गैर नुकसानदेह और अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी, यह बजट साफतौर पर उसका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। साथ ही इसमें विकास एवं रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया है। भारत कैसे 'कम से कम सरकार और अधिक से अधिक प्रशासन' की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो, इसकी राह भी इस बजट से खुलती दिख रही है। देश के बाहर और भीतर काला धन उत्पादन के स्रोत पर चोट करने की मंशा भी इसमें साफ झलक रही है। यह बजट वंचित तबकों को सामाजिक सुरक्षा का कवच मुहैया कराता भी प्रतीत हो रहा है। इसमें आर्थिक स्थिरता हासिल करने की प्रबल इच्छाशक्ति भी दिखाई दे रही है। बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रस्ताव से आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होने के साथ रोजगार सृजन की संभावना भी बनेगी। खेती–किसानी को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव कृषि के विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। कौशल विस्तार के साथ–साथ विकास पर भी इसमें बल दिया गया है। बजट प्रस्तावों के द्वारा वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने देश को 'एक समृद्ध राष्ट्र और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति' बनाने की उम्मीद जगाई है।

निष्कर्ष

अंत में यह कहा जा सकता है कि इस बार केन्द्रीय बजट पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कृषि के प्रति प्रतिबद्धता साफ दिखाई दे रही है। वित्तमंत्री ने कृषि उत्पादकता, सिंचित क्षेत्र बढ़ाने व कृषि संबंधी योजनाओं की कार्यकुशलता व किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया। मिट्टी व पानी के सदुपयोग के लिए स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड के साथ–साथ परम्परागत कृषि योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। सिंचाई क्षमता व खेत की जलधारण करने की क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए 5300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि विकास के लिए आम बजट में 3257 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह डेयरी विकास के लिए 481 करोड़, नीली क्रांति के लिए 411 करोड़ के अतिरिक्त कृषि बीमा के लिए 2586 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना के लिए बजट में राज्यों के साथ मिलकर काम करने की भी घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए 3295 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल: savitakumari470@yahoo.com

बजट : 2015–16

सशक्त कृषि संचार 'प्रति बूंद, अधिक फसल' का आधार

—उमाशंकर मिश्र एवं सुबोध कुमार

खेतों के लिए पानी जरूरी है, मगर कृषि प्रधान देश भारत में आज भी किसान बरसात के भरोसे पर ही रहते हैं। सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार का 'प्रति बूंद, अधिक फसल' अभियान निश्चित तौर पर एक बेहतर प्रयास कहा जा सकता है। मगर, सशक्त कृषि संचार के बिना इसके लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा।

करीब 49 प्रतिशत भारत की श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हालांकि आर्थिक सर्वे 2014–15 के मुताबिक कृषि की विकास दर इस साल महज एक प्रतिशत ही थी। आर्थिक सर्वे में इन आंकड़ों के आधार पर सरकार के लिए भावी चुनौतियों का जिक्र किया गया है। वर्ष 2013–14 में 265.6 मीट्रिक टन अनाज उत्पादन हुआ था, जो इस साल फिसलकर 257.1 मीट्रिक टन पर पहुंच सकता है। यह सही है कि बीते साल में जून से लेकर सितंबर तक मानसून की बरसात करीब 12 प्रतिशत कम हुई थी। मगर, कृषि विकास दर में हुई गिरावट को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। खासतौर पर ऐसे वक्त में जबकि बढ़ती आबादी और शहरीकरण से भविष्य में खाद्यान्न संकट की आहट साफ सुनाई दे रही है।

कृषि एवं खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक समीक्षा में अनुसंधान, सिंचाई और भंडारण जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय साझा बाजार

बनाने का भी आह्वान किया गया था। खेतों की सिंचाई के लिए बरसात पर निर्भरता आज भी भारत में कम नहीं हुई है। देश के शुद्ध बोए गए करीब 52 प्रतिशत भू–भाग की मात्र 28 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार कुल कृषि भूमि के लगभग 72 प्रतिशत भाग पर की जाने वाली कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। मानसून की बरसात भारत में काफी मायने रखती है, क्योंकि भारत की दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का 14 प्रतिशत योगदान बेहद अहम है। इसीलिए बरसात की उम्मीद करके और खेतों को प्यासा रखकर कृषि को रामभरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। देश की करीब आधी असिंचित भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं का प्रबंध किए बिना कृषि की बेहतरी का सपना देखना भी बेमानी है। कमजोर मानसून के कारण न केवल कृषि उत्पादन कम होता है, बल्कि महंगाई भी आसमान छूने लगती है। इस बार जैसे ही मौसम विभाग ने बेहतर मानसून रहने की भविष्यवाणी की, तो उधर आरबीआई ने भी रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया। जाहिर है अर्थव्यवस्था का पूरा चक्र कहीं न कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है। सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है और अर्थशास्त्री भी इस बात को मानते हैं कि कृषि की बेहतरी के बिना गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता।

कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण दो प्रमुख कारकों– मिट्टी और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्री ने कृषि मंत्रालय की जैविक खेती योजना– 'परंपरागत कृषि विकास योजना के वित्तपोषण और उसे सहायता देने का प्रस्ताव भी किया है।

बेशक उत्पादन बढ़ाकर ही खाद्यान्न की बढ़ती मांग की पूर्ति संभव है। शहरीकरण और औद्योगीकरण के लिए बढ़ते भूमि अधिग्रहण तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती मौसम की अनिश्चितताओं के मद्देनजर खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। बदलते वक्त में किसान को स्मार्ट बनाने की जरूरत है, ताकि वो बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल सकें। इसके लिए कृषि संचार के सशक्त विकल्पों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कृषि संचार को प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। किसानों तक मोबाइल डिवाइसेज की पहुंच, उनके इस्तेमाल एवं विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, खेती–किसानी से जुड़ी सफलता की कहानियों का प्रेषण, नए प्रयोग एवं नई तकनीक की जानकारी डिजिटल प्लेटफार्म पर सुनिश्चित होनी चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इन चुनौतियों की ओर इशारा किया, बल्कि उससे निपटने के लिए प्रयोगशाला से खेत और 'प्रति बूंद, अधिक फसल' का नारा भी दिया। आजादी के 66 साल बाद भी हमारी खेती सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। बजट में सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को मजबूत बनाने के मकसद से सूक्ष्म सिंचाई, जल संभरण विकास और 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के लिए 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन करके अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। आम बजट में सिंचाई योजना के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' पर जोर दिया गया है। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2015–16 प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि 'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना' का लक्ष्य हर एक किसान के खेत को सींचना और 'प्रति बूंद अधिक फसल' की व्यवस्था करने के लिए पानी का प्रभावी इस्तेमाल करना है। श्री जेटली ने राज्यों से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर योगदान देने का अनुरोध किया है। वित्तमंत्री ने कहा, हमारे किसानों के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता है।

अब जबकि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप मानसून की अनिश्चितता और भी बढ़ गयी है। ऐसे में जलसंचय और उसकी एक–एक बूंद का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। कम समय और कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा फसल के जरिए ही अब उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शहरीकरण और औद्योगीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के चलते उपजाऊ कृषि भूमि का विस्तार तो संभव ही नहीं है, उलटे वह कम ही होती जा रही है। मेहनत का पर्याप्त प्रतिफल न मिल पाने के कारण किसान तेजी से कृषि से मुंह मोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह सोच बिलकुल सही है कि किसानों को मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलना चाहिए, ताकि उनकी जेब भर सके। यह तभी हो सकेगा, जब कृषि उत्पादन के साथ ही भंडारण, बाजार और वितरण की व्यवस्था भी बेहतर बनाई जाए। कम क्षेत्रफल में कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कैसे हो, यह खोजने और किसानों को बताने–समझाने का काम कृषि वैज्ञानिकों का ही है। इसीलिए श्री मोदी ने प्रयोगशाला से खेत की बात कही है। कृषि अनुसंधान पर भी अरसे से जोर दिया जाता रहा है, लेकिन हरितक्रांति के बाद उससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए अक्सर दूसरी हरितक्रांति की जरूरत पर जोर दिया जाता रहा है। ऐसे ही दूसरी श्वेतक्रांति की जरूरत भी बतायी जाती रही है। खेती और पशुपालन पारस्परिक रूप से एक–दूसरे पर आश्रित हैं। किसानों की आजीविका में इन दोनों

ही संसाधनों का अहम योगदान है। मगर, पानी की उपलब्धता के बिना न तो खेती संभव है और न ही पशुपालन।

'प्रति बूंद–अधिक फसल' अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे चीन की तरह औषधीय पौधों पर ध्यान केंद्रित करें। मौसम चक्र में बदलाव के मद्देनजर वर्षा जल संचयन और अन्य पहलुओं के जरिए जल संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के सुझावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्री मोदी ने कहा है कि 'सुनिश्चित करें कि एक बूंद भी बर्बाद न हो, देश में जलसंकट से निपटने की आवश्यकता है, मौसमी चक्र में बदलाव के मद्देनजर जल प्रबंधन करें, आईसीएआर, समुद्री शैवालों के लिए व्यापक शोध और संवर्धन करे और आईसीएआर अगले 14 साल में ज्यादा उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करें।

दुनिया भर में औसत रूप से पानी की 70 प्रतिशत खपत कृषि में होती है। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पानी कृषि क्षेत्र के संरक्षण के उपायों का केंद्रबिंदु होना चाहिए। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र ने सूखे को दुनिया की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा माना है। आर्थिक दृष्टि से इसकी वार्षिक लागत 6–8 बिलियन डॉलर आंकी गई है और मानवीय दृष्टि से सूखे ने सन् 1900 से लेकर अब तक दो बिलियन लोगों को प्रभावित किया है। इस दौरान करीब 11 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु सूखे के कारण हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा असुरक्षित है। सूखे के प्रभावित क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और मध्य–पूर्व के देश मुख्य रूप से शामिल हैं। इसरो के मुताबिक दो सदी से भी अधिक समय (1801 से 2002) के बीच भारत में 42 बार भीषण सूखा पड़ चुका है। इनमें से एक सूखा 1979 में पड़ा था, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। जबकि 1987 में पड़े सूखे के कारण 58.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि बेकार हो गई और करीब 285 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे। पिछले दशक (2002–2012) के दौरान देश को तीन बार भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। 2013 की विश्व बैंक रिपोर्ट में भी माना गया है कि 2012 में सूखे के कारण भारत की जीडीपी में भारी गिरावट हुई थी।

भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 करोड़ हेक्टेयर है, जिसके 92.2 प्रतिशत के भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं। लगभग 51 प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत आता है, जबकि लगभग 4 प्रतिशत भूमि पर चारागाह, 21 प्रतिशत भूमि पर वन तथा 24 प्रतिशत भूमि बंजर अथवा बिना किसी उपयोग की है। 24 प्रतिशत बंजर भूमि में 5 प्रतिशत परती भूमि भी शामिल है, जिसमें प्रतिवर्ष फसलें न बोकर तीसरे या पांचवें वर्ष बोयी जाती हैं, जिससे भूमि की उर्वरता संचित हो सके। इस शुद्ध बोए गए 52 प्रतिशत भू–भाग के मात्र 28 प्रतिशत भाग अर्थात् 4.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है, जबकि देश का समस्त सिंचित क्षेत्र 8 करोड़ हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल कृषि भूमि के लगभग 72 प्रतिशत भाग पर की जाने वाली कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग पर सिंचाई के छोटे साधनों– कुएं, तालाब, झीलें, जलाशय, बांध, नलकूप, मिट्टी के कच्चे बांध, नल तथा जल स्रोतों द्वारा सिंचाई की जाती है। शेष भाग की सिंचाई बड़े साधनों, यथा– नहरों, नालियों आदि के माध्यम से की जाती है। भारत में सूखा और सिंचाई सुविधाओं की बात इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इनमें से 58 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से सिर्फ कृषि पर निर्भर हैं। इनमें बहुसंख्य आबादी गरीबी–रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले किसानों की है। रंगराजन समिति के मुताबिक भारत की कुल आबादी के 29.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर हैं। समाज के इन वंचित वर्गों को विकास की धारा में शामिल किए बिना समावेशी विकास और सशक्त लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

दुनिया के कई हिस्सों में सूखा–प्रतिरोधी जीई फसल की किस्में विकास प्रक्रिया में से उभर कर आ रही हैं। पिछले दो दशकों में ऐसी फसलों की खेती लगभग 30 देशों के 17 मिलियन से अधिक किसानों द्वारा 1.5 बिलियन हेक्टेयर रकबे में की गई है। हालांकि दुनिया भर में कृषि में जीई यानी

जेनेटिक इंजीनियरिंग को अनुसंधान और विकास कार्य में कार्यकर्ताओं के प्रतिरोध और सरकार के अत्यधिक विनियमन के फलस्वरूप बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। जबकि जेनेटिक फसलों के उपयोग से पानी के किफायती उपयोग और बेहतर आर्थिक मुनाफे का दावा करने वाले भी कम लोग नहीं हैं। दुनिया भर में सिंचित भूमि का एक–तिहाई भाग नमक की उपस्थिति के कारण फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त नहीं बचता है। वैज्ञानिकों ने टमाटर और कनोला जैसी विविध प्रकार की फसलों में नमक की सहिष्णुता में वृद्धि की है। दावा किया जाता है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे खारी मिट्टी में विकसित हो सकते हैं और उनकी खारे पानी से सिंचाई की जा सकती है, जिससे ताजे जल का अन्य उपयोगों के लिए संरक्षण किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा एक प्रमुख खतरा पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रकृति के बनाए हुए पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बिगाड़ कर रख सकती है। इन तमाम सवालों को संतुलित ढंग से आम जनमानस तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि बाजार और सरकार की कोई भी जनविरोधी नीति लोगों को गुमराह न कर सके। इस काम को पूरा करने के लिए कृषि संचार के संसाधनों को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।

जैसे–जैसे जल की कमी बढ़ेगी, सूखे से प्रभावित फसलें सूखने लगेंगी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसके फलस्वरूप लोचदार कृषि की आवश्यकता और अधिक हो जाएगी। ऐसे में अधिक तर्कसंगत सार्वजनिक नीति के साथ, हम उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। 'प्रति बूंद, अधिक फसल' का संदेश साफ है कि पानी का कुशलता से खेती में उपयोग किया जाए। इसके लिए सिंचाई के संसाधनों, तकनीकों और जल–संरक्षण के उपायों की किसानों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है। लेकिन अब तक का सबक यही रहा है कि सही सूचनाओं, उपयुक्त तकनीक और बदलते वक्त की जरूरतों की जानकारी के अभाव में हमारे किसान पिछड़े हुए हैं। किसानों को स्मार्ट बनाने के लिए उन तक योजनाओं की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। किसानों को सूचना से सशक्त बनाने में गैर –सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सामुदायिक रेडियो, समाचार–पत्रों, परिचर्चा, वर्कशॉप, डॉक्युमेंट्री जैसे संचार उपक्रमों की भूमिका काफी अहम साबित हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को माना है कि देश की जनता तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों को अपने यहां रेडियो स्टेशन स्थापित करने का सुझाव दिया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने प्रगतिशील किसान और कृषि शोध में लगे विद्वानों को मिलकर अच्छा समूह बनाने की बात भी कही है। इसके अलावा उन्होंने आईसीएआर को अगले चार–पांच वर्षों के दौरान देश में सभी कृषि शोधों के आंकड़ों का डिजिटलीकरण करने के लिए भी कहा है। इन प्रयासों से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

लेखक क्रमशः वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (कोटा) में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के शोधार्थी एवं संयोजक हैं।
ई–मेल : Email : skumar@vmou-ac-in

बजट : 2015–16

बजट में पर्यटन विकास पर जोर

—नवनीत रंजन

केंद्र सरकार की ओर से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आम बजट के साथ ही रेल बजट में भी विदेशी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय पर्यटकों का ध्यान रखा गया है। इससे भविष्य में भारत में पर्यटन और अधिक समृद्धशाली हो सकता है। विदेशी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय पर्यटकों के आवागमन की न सिर्फ गति बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा भी मिलने की संभावना है। पर्यटन विभाग के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत के पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटकों का रुझान बढ़ा है। ऐसे में सरकार दो कदम आगे रहना चाहती है। सरकार की मंशा है कि भारत के पर्यटन स्थलों का विकास करने के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को भी समुचित सुविधा मुहैया कराई जाए।

भारत सरकार की ओर से ग्रामीण पर्यटन को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत जहां तमाम उपक्रम किए गए हैं वहीं इस बार के बजट में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। खासतौर से ग्रामीण पर्यटन को गति मिलेगी। इसी उद्देश्य से वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने 43 देशों के यात्रियों को आगमन पर वीजा देने की सुविधा की सफलता के बाद 150 देशों के यात्रियों को यह सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। इससे भारतीय पर्यटन उद्योग को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा बल्कि उद्योग के नए रास्ते भी खुलेंगे। वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में विविधताएं मौजूद हैं। यहां की सांस्कृतिक धरोहरों और सांस्कृतिक पर्यटन की चर्चा पूरे विश्व में होती है। इसी के तहत उन्होंने विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के जीर्णोद्धार की घोषणा की। भारत में इस समय 32 विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की तरफ से मान्यता मिली हुई है। इसके साथ ही बजट में कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, और वियतनाम देशों में विनिर्माण केंद्रों के गठन की भी घोषणा की गई है।

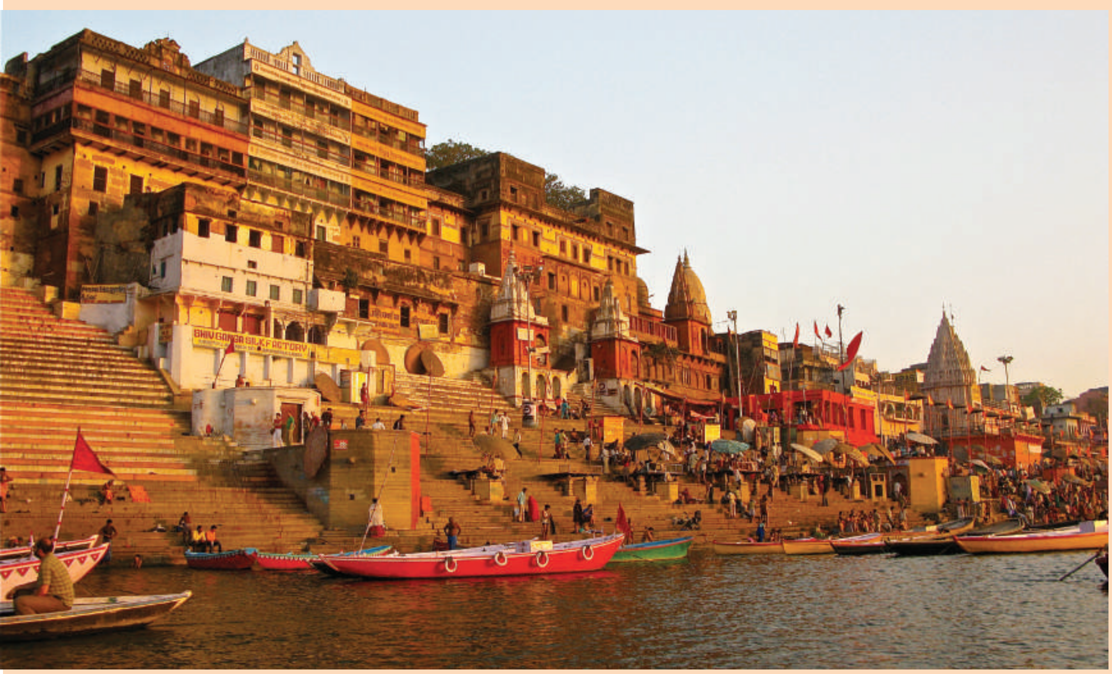

सत्तासीन होते ही सरकार के प्राथमिकता वाले एजेंडे में 'पर्यटन' शामिल हो गया। पिछले दिनों लोकसभा में एक सवाल के जवाब में पर्यटन राज्यमंत्री डा. महेश शर्मा ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के प्रति आचरण और व्यवहार के संबंध में जन सामान्य के साथ–साथ पर्यटन उद्योग के हितधारकों को संवेदनशील बनाने

के लिए अतिथि देवो भव–सामाजिक जागरुकता अभियान चलाया है। इतना ही नहीं पर्यटन स्थलों को संरक्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन स्थलों के बारे में पर्यटकों के साथ ही आम जनता को भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। समृद्धिशाली ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के साथ ही धार्मिक स्थलों को लेकर भी पर्यटकों का रुझान बढ़ा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से दिसंबर, 2012 की अपेक्षा वर्ष 2013 में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में करीब 5.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या करीब 69.68 लाख रही। यह संख्या वर्ष 2014 में बढ़कर 74.62 लाख हो गया। यानी वर्ष 2013 की अपेक्षा वर्ष 2014 में विदेशी पर्यटकों के आगमन का आंकड़ा 7.1 फीसदी बढ़ा। जिस गति से पर्यटकों की संख्या बढ़ी, उसी गति में भारत में विदेशी मुद्रा भी आई। 2012 की अपेक्षा वर्ष 2013 में 10,7671 करोड़ रुपये की विदेशी आय हुई। जबकि 2013 की अपेक्षा 2014 में पर्यटन क्षेत्र से विदेशी मुद्रा आय में करीब 11.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

इस तरह देखा जाए तो भारत में विदेशी पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। साथ ही स्थानीय पर्यटक भी अलग–अलग इलाके में भ्रमण में रुचि दिखा रहे हैं। स्थानीय पर्यटक जहां पूरब से पश्चिम इलाके का भ्रमण् कर रहे हैं वहीं उत्तर के पर्यटक दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित हैं। पर्यटकों की इस अभिलाषा को देखते हुए सरकार ने भी कदम से कदम मिलाकर सहयोग करने की प्रवृत्ति अपनाई है। भारत सरकार के विदेशी मामले के मंत्रालय के नोआखाली (बांग्लादेश) में गांधी आश्रम ट्रस्ट के उन्नयन के प्रस्ताव को गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह भारतीय दूतावास द्वारा दक्षिण अफ्रीका को ऐतिहासिक पीटर मारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक स्थायी प्रदर्शनी की स्थापना के लिए दिए गए प्रस्ताव को गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

सर्किट विकास पर जोर

केंद्र सरकार की ओर से भारत में पर्यटन की अपार संभावनाओं और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय की ओर से थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का विकास किया जा रहा है। इसके तहत एकीकृत विकास–स्वदेश दर्शन और तीर्थ जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पीआरएसएडी) पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। भारत सरकार ने विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल आथोराइजेशन समर्थित आगमन पर पर्यटक वीजा आरंभ किया है। यह सुविधा भारत में नौ हवाई अड्डों पर दी जा रही है। ये हवाई अड्डे हैं–दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलूरू, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और गोवा। यह सुविधा 44 देशों से आने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई है ताकि उन्हें भारत आगमन के बाद किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

ताजमहल और हुमायूं के मकबरे पर ई–टिकटिंग

आगरा में ताजमहल और दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर ई–टिकटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे आईआरसीटीसी की मदद से किया जा रहा है। प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत के बाद देशभर में अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर ई–टिकटिंग शुरू कर दी जाएगी। इन स्थानों पर इस सुविधा के बहाल होने का सकारात्मक असर दिखाई पड़ने लगा है। इससे सैलानियों को सहूलियत मिली है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति

भारत में पर्यटकों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से नई पर्यटन नीति भी तैयार की गई है। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावना बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। नई पर्यटन नीति 2015 के लिए सुझाव मांगे गए हैं। सरकार की कोशिश है कि यह पर्यटन नीति ऐसी तैयार हो, जिससे पर्यटक स्थल का समुचित विकास होने के साथ ही वह स्थल रोजगार का केंद्र बने। इसके साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इससे पहले वर्ष 2002 में पर्यटन नीति तैयार की गई थी। सरकार की कोशिश है कि नई पर्यटन नीति में इस 13 वर्ष के अंतराल में बढ़ी सुविधाओं को समाहित किया जाए।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना

केंद्र सरकार की ओर से विदेशी पर्यटकों के साथ ही ग्रामीण पर्यटन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की कला एवं शिल्प, हस्तकरघा, वस्त्र, प्राकृतिक पर्यावरण आदि में मूलभूत क्षमता रखने वाले गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के मुख्य उद्देश्य से एक ग्रामीण पर्यटन योजना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके द्वारा पहचाने गए प्रत्येक स्थल के लिए अवसंरचना विकास के लिए 50 लाख रुपये तक की और क्षमता बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपये तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट

केंद्र सरकार ने पर्यटन विकास के लिए न सिर्फ आम बजट में तमाम प्रावधान किए हैं बल्कि रेल बजट में भी पर्यटन का खासा ध्यान रखा गया है। रेल बजट पेश करते हुए रेलमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल अतुल्य भारत के लिए इस अतुल्य रेल प्रयास में अपना सहयोग प्रदान करेगी। ऑटोरिक्शा तथा टैक्सी चालकों को पर्यटन गाइडों के रूप में प्रशिक्षित करके कोंकण रेलवे में पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सफल प्रयोग किया गया है क्योंकि सबसे पहले यही लोग यात्रियों के संपर्क में आते हैं। इसके साथ ही राजस्व की भागीदारी मॉडल के आधार पर ट्रैवल एजेंसियों को प्रमुख स्थलों को जोड़ने वाली चुनिंदा गाड़ियों में कुछ सवारी डिब्बे देने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव है। रेलमंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आईआरसीटीसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी संर्किट को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। नई खेती और विपणन तकनीक के बारे में किसानों की सहायता के लिए आईआरसीटीसी एक विशेष यात्रा योजना 'किसान यात्रा' पर कार्य करेगी।

सरकार की एक्ट ईस्ट नीति

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, और वियतनाम नामक सीएमएलवी देशों में विनिर्माण केंद्रों के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट नीति दक्षिण–पूर्वी एशिया में सघन आर्थिक और कार्यनीति संबंधों को बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। इस क्षेत्र में भारतीय निजी सेक्टर से निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए, परियोजना विकास कंपनी सीएमएलवी देशों में पृथक विशेष प्रयोजन साधनों के माध्यम से विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करेगी।

विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का जीर्णोद्धार

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए ग्रामीण पर्यटन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम इलाकों में ऐसी धरोहरें हैं, जो ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही सांस्कृतिक समरसता को बढ़ा रही हैं। देश के ऐसे 25 विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थलों पर सुविधाओं की अभी भी कमी है और उनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इन स्थानों पर सुरक्षा और शौचालय, प्रकाश व्यवस्था मुकम्मल की जाएगी। साथ ही धरोहर स्थल के आसपास के समुदाय के लिए लाभ की योजनाओं सहित भू–सौन्दर्यीकरण, द्विभाषीय केंद्रों, पार्किंग, निशक्तजनों और आगन्तुकों के लिए सुविधाओं जैसे कार्यों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि जिन आठ स्थलों को जीणोद्धार के लिए चयनित कर लिया गया है, वह निम्नलिखित हैं–

- पुराने गोवा के गिरिजाघरों और कॉन्वेन्ट्स
- हम्पी, कर्नाटक
- कुम्भलगढ़ और राजस्थान के अन्य किले
- रानी की वाव, पाटन, गुजरात
- लेह पैलेस, लद्दाख, जम्मू–कश्मीर
- वाराणसी शहर के मंदिर, उत्तर प्रदेश
- जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब
- कुतुबशाही मकबरा।

पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से उठाए गए अन्य प्रमुख कदम

डाक नेटवर्क को बढ़ावा

भारत के ग्रामीण इलाके में डाक सेवा को सबसे बेहतर माना जाता है। ग्रामीण इलाके में कूरियर जैसी व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्ट्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डाकघरों का मार्डनाइजेशन भी है। देशभर में फैले डाक नेटवर्क का उपयोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इस संदर्भ में सरकार ने देश के गांव में फैले करीब 1,54,000 केंद्रों के साथ विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है। वित्तमंत्री ने कहा कि डाक विभाग अपने प्रस्तावित बैंक भुगतान उद्यम को सफल बनाएगा जिससे प्रधानमंत्री जन–धन योजना में लाभ मिलेगा। साथ ही विभिन्न इलाकों से संबंधित गांव में पहुंचने वाले पर्यटकों को भी हर तरह की सुविधा मिल सकेगी।

अटल नवाचार मिशन की स्थापना

केंद्रीय वित्तमंत्री ने नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन (एआईएम) की स्थापना करने की मंशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा एआईएम एक नवाचार संवर्द्धन मंच होगा, जिसमें शिक्षाविद्‌ों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और भारत में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा वैज्ञानिक शोध की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाया जाएगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण पलायन थमेगा। प्रारंभ में इस उद्देश्य के लिए एक सौ पचास करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी।

(लेखक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़े हैं।)
ई–मेलः navneetrnjn955@gmail.com

सिविल सेवा परीक्षा '15

CSAT
की तैयारी
Career Launcher,
National #1, के साथ

प्रत्येक वर्ष 10 लाख से भी अधिक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए CL को चुनते हैं

- शिक्षण, परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए 250+ घंटों की कक्षाएं
- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 12 मॉक टेस्ट (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I एवं II)
- बोधगम्यता तार्किक कौशल और आधारभूत गणित पर विशेष बल
- 24×7 स्टूडेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SIS) पर विश्लेषण एवं मार्गदर्शन की ऑनलाइन सहायता
- R&D टीम तथा फैकल्टी सदस्य जिन्होंने स्वंय सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है
- विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी व्यापक अध्ययन सामग्री
- नियमित मॉड्यूल एवं रिवीज़न टेस्ट
- पर्सनल डाउट सेशन

1069 CL अभ्यर्थी सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा '14 के लिए योग्य पाये गये

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

/CLRocks

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज एवं CSAT के नये बैच शीघ्र प्रारंभ
जानकारी के लिए अपने निकटतम् CL केंद्र पर संपर्क करें!

मुखर्जी नगरः 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगरः 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन – 42375128/29
बेर सरायः 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन – 26566616/17
ग़ाज़ियाबादः सी–27, द्वितीय तल, आरडीसी मार्केट, राज नगर, (बीकानेर स्वीट्स के सामने) फोन – 0120–4380996

इलाहाबादः 19 बी/49, भूतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन – (0)9956130010

"CL Educate Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its equity shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in and the website of Kotak Mahindra Capital Company Limited at www.investmentbank.kotak.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the Draft Red Herring Prospectus, including the section titled "Risk Factors".

KH-387/2014

रेल बजट में ढांचागत मजबूती के प्रयास

—मनोज श्रीवास्तव

रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा करने के बजाय रेलवे को गतिशील बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही तमाम ऐसे प्रयास किए हैं, जिससे भविष्य की रेलवे फुल स्पीड से दौड़ती नजर आएगी। उन्होंने यात्री भाड़े में बढ़ोतरी न करके यात्रियों को बड़ी राहत दी है।

बजट में किसी नई ट्रेन या नई लाइन और यात्री किराये में किसी तरह के बदलाव की घोषणा न कर रेलमंत्री का जोर ढांचागत बदलाव में अधिक दिखा। खुद रेलमंत्री रेल बजट को नीतिगत बयान की तरह देखते हैं और उन्होंने रेलवे को निवेश का बड़ा जरिया बनाने के लिए पांच वर्ष का खाका पेश किया है, जिसके तहत साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश की पेशकश उन्होंने की है। रेलमंत्री ने यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए वाई–फाई से लेकर चलती ट्रेन में सीटों की ताजा स्थिति तक ऑनलाइन देखने की सुविधा देने की घोषणा की है, जोकि देश में मोबाइल इंटरनेट फोनधारकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक अच्छी पहल कही जा सकती है। रेल बजट में योजना बजट के आकार में 52 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह 2014–15 के 65,798 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015–16 में 1,00,011 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें केंद्र सरकार से कुल योजना बजट 41.6 फीसदी और आंतरिक सृजन के लिए हेतु 17.8 फीसदी की सहायता मिली है। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड में एक वित्त व्यवस्था कक्ष की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाएगा।

बजट पेश करते हुए रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु ने स्वामी विवेकानंद ने उस कथन का जिक्र किया, जिसमें स्वामीजी ने कहा था कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में ही सोचो, उसका सपना देखो। उसी विचार पर जियो।

अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उस विचार को भर दो और अन्य विचारों को न आने दो, यही सफलता की कुंजी है। रेलमंत्री ने कहा कि स्वामीजी का यही कथन उनके लिए भारतीय रेलवे की कायापलट से है। हम रेलवे का कायापलट कर देंगे। वास्तव में भारतीय रेल की बुनियादी समस्या उसके आधारभूत ढांचे का बेहतर न होना है। रेलमंत्री ने इसके लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। बजट में भारतीय रेलवे को एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक बनाने के उपाए सुझाए गए हैं। इसमें उच्च निवेश, भारी बोझ वाले मार्गों पर भीड़–भाड़ में कमी लाने और रेलगाड़ियों और अन्य परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया है। साथ ही बेहतर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा तथा रेलवे को जनता के लिए यातायात का पसंदीदा माध्यम बनाने के लिए संसाधन जुटाने की बात कही गई है।

नागरिकों के लिए रेल यात्रा के महत्व को देखते हुए, भारतीय रेलवे यात्री वहन क्षमता 21 मिलियन यात्री प्रति दिन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक की जाएगी। साथ ही रेलपथ की लंबाई भी 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर 1,14,000 कि.मी. से 1,38,000 कि.मी. तक की जाएगी और वार्षिक मालवाहक क्षमता को एक बिलियन टन से बढ़ाकर 1.5 बिलियन टन किया जाएगा। रेलमंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि उन्होंने चार लक्ष्य पर खास जोर दिया हैं। इसमें ग्राहकों के अनुभव में स्थायी और मापन योग्य सुधार लाना, रेलवे को यात्रा का सुरक्षित साधन बनाना, भारतीय रेलों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करना और उसकी अवसंरचना को आधुनिक बनाना है। इनके लिए उन्होंने पांच कारकों का सुझाव दिया है। इसमें श्वेतपत्र, विज़न–2030 दस्तावेज और पंचवर्षीय कार्ययोजना सहित मध्यावधि योजना अपनाने का प्रस्ताव शामिल है। दीर्घकालिक वित्त एवं विदेशों से प्रौद्योगिकी, संपर्क में सुधार लाने, चल स्टॉक में विस्तार और स्टेशन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी की जरूरत होगी।

भारतीय रेलवे अतिरिक्त संसाधनों पर भी बल देगा, उसका अगले पांच वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का विचार है। यात्री सुविधाओं का जिक्र करते हुए रेलमंत्री ने अनारक्षित टिकट का भी ध्यान रखा है। अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने के इच्छुक आम आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या टिकट खरीदने की होती है। अनारक्षित यात्रा करने वाला यात्री 5 मिनट के भीतर टिकट खरीद सके, यह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन फाइव मिनट शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। बहादुर सिपाहियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए वारंट को समाप्त करने के लिए रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है। लगभग 2000 स्थानों में से 600 स्थानों पर इस सुविधा को चालू कर दिया गया है। इस सुविधा का और विस्तार किया जाएगा। ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) और निचले सड़क पुल (आरयूबी) के निर्माण कार्य में तेजी लाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अगले वित्तवर्ष में 6581 करोड़ रुपये के कुल रेल खर्च की लागत पर आरओबी/आरयूबी के 970 निर्माण कार्य तथा 3438 समपारों को समाप्त करने के लिए संरक्षा संबंधी अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। यह चालू वित्तवर्ष से 2600 प्रतिशत अधिक है और वर्तमान समय में सबसे अधिक है।

खानपान का ध्यान

रेल यात्रियों को भोजन चुनने के लिए विकल्प दिए गए हैं। इसमें स्थानीय व्यंजन भी शामिल हैं। यात्री अपने पसंद का भोजन चुन सके, इसके लिए जनवरी से प्रायोगिक तौर पर 108 गाड़ियों में ई–केटरिंग शुरू की गई है। यदि यह बेहतर रही तो इसे अन्य ट्रेनों में भी शुरू करने की बात कही गई है। इस सुविधा के जरिए यात्री टिकट को बुक करते समय आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से अपने भोजन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। देश की सर्वोत्तम फूड चेनों को इस परियोजना में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट मंडलों में बेस किचन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिन्हें अत्यंत विश्वसनीय एजेंसियों द्वारा चलाया जाएगा।

ई– योजनाओं पर खास जोर

रेलमंत्री ने बजट में ई–गवर्नेंस पर खासा जोर दिया है। चल टिकट परीक्षकों को हैंड हेल्ड टर्मिनल उपलब्ध कराए जाएंगे जिनका उपयोग यात्रियों का सत्यापन और चार्टों को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकेगा। इस प्रणाली से पेपरलैस टिकटिंग और चार्टिंग की ओर अग्रसर होने और इससे पेपर के रिमों की बचत होने के अलावा रिफंड के दावों को अंतिम रूप देने में भी तेजी लाने में सहायता मिलेगी। इसी तरह केंद्रीय रूप से नियंत्रित रेलवे डिस्पले नेटवर्क को अगले दो वर्षों में 2000 से ज्यादा स्टेशनों पर लागू कर देने की संभावना है, जो गाड़ी के आगमन/प्रस्थान, आरक्षण, सामान्य तथा आपात संदेशों तथा नागरिकों की रुचि की किसी अन्य सूचना को भी मुहैया कराने में सहायता प्रदान करेगा।

एसएमएस सेवा

यात्रियों को पहले ही प्रारंभिक अथवा गंतव्य स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के अद्यतन समय की जानकारी देने के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। इसी

प्रकार, गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के आगमन से 15/30 मिनट पहले एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पायलट आधार पर मेनलाइन के चुनिंदा सवारी डिब्बों और उपनगरीय गाड़ियों में महिलाओं के डिब्बों में निगरानी रखने के लिए कैमरा लगाए जाएंगे परंतु ऐसा करते समय उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली मंडल चुनिंदा शताब्दी गाड़ियों में लाइसेंस शुल्क के आधार पर ऑनबोर्ड मनोरंजन की एक परियोजना की शुरुआत कर रहा है। साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बों में मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी और स्लीपर श्रेणी के सवारी डिब्बों में चार्जिंग सुविधाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी। वहीं पहले जहां दो माह पूर्व से टिकट आरक्षण कराने की सुविधा थी वहीं इसमें ढील देते हुए चार माह पहले आरक्षण कराने की सहूलियत दे दी गई है।

ट्रेनों के साथ स्टेशनों का विकास

आदर्श स्टेशन स्कीम के अंतर्गत यात्री सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 200 ओर स्टेशनों को शामिल करने का प्रस्ताव है। स्टेशनों पर धीरे–धीरे स्वयं परिचालित किए जाने वाले लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। गाड़ियों में कंर्फम सीटों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करके अधिक सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। ऊपरी बर्थ चढ़ने के लिए असुविधाजनक के स्थान पर सुविधाजनक सीढ़ियों की व्यवस्था की जाएगी।

महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल

रेल बजट में महिलाओं के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का भी ख्याल रखा गया है। अब भारतीय रेलवे महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया निधि के संसाधनों का उपयोग करेगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पायलट परियोजना के तहत प्रमुख चुनिंदा और महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस दौरान यात्रियों की निजता के साथ समझौता नहीं होगा। इसी तरह रेलमंत्री ने बजट पेश करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि चल टिकट परीक्षकों को निचली बर्थ प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और भिन्न रूप से सूक्षम व्यक्तियों की मदद करने की हिदायत दी जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवारी डिब्बे के मध्य भाग में सीटें आरक्षित की जाएगी।

अतुल्य भारत का सपना

भारतीय रेल अतुल्य भारत के लिए इस अतुल्य रेल प्रयास में अपना सहयोग प्रदान करेगी। ऑटोरिक्शा तथा टैक्सी चालकों को पर्यटन गाइडों के रूप में प्रशिक्षित करके कोंकण रेलवे में पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सफल प्रयोग किया गया है क्योंकि सबसे पहले यहीं लोग यात्रियों के संपर्क में आते हैं। राजस्व की भागीदारी मॉडल के आधार पर ट्रैवल एजेंसियों को प्रमुख स्थलों को जोड़ने वाली चुनिंदा गाड़ियों में कुछ सवारी डिब्बे देने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव है।

किसान यात्रा

बजट पेश करते हुए रेलमंत्री ने कहा कि इस वर्ष जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है,आईआरसीटीसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। ऐसी स्थिति में नई खेती और विपणन तकनीक के बारे में किसानों की सहायता के लिए आईआरसीटीसी एक विशेष यात्रा योजना किसान यात्रा पर कार्य करेगी।

सुरक्षा चेतावनी प्रणाली और गाड़ियों की टक्कर से बचाव की प्रणाली

रेलमंत्री ने रेल बजट 2015–16 पेश करते हुए कहा कि चुनिंदा मार्गों पर जल्द ही रेल सुरक्षा चेतावनी प्रणाली और गाड़ियों की टक्कर से बचाव की प्रणाली लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सवारी डिब्बों में आग की रोकथाम और दुर्घटना के समय सवारी डिब्बों। को एक–दूसरे के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए आरडीएसओ को नई प्रणालियां विकसित

करने का प्रस्ताव रखा है। रेलमंत्री ने संसद में बताया कि गाड़ियों को पटरी से उतरने से रोकने के लिए, रेल पथ का प्राथमिक नवीनीकरण करते समय स्लीपर और भारी पटरियों वाली आधुनिक रेलपथ संरचना का उपयोग किया जा रहा है। वेल्डिंग की बेहतर तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, पटरियों की जांच के लिए एनालॉग मशीनों को अधिक विश्वसनीय डिजिटल किस्म की मशीनों से बदला जा रहा है।

चार रेलवे रिसर्च इंस्टीट्यूट

वैश्विक मानदंडों के मुताबिक रेल कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार 2015–16 के दौरान रेलवे विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी में है। इसके अलावा सरकार कुछ चयनित विश्वविद्यालयों में चार रेलवे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोलेगी। रेल कर्मचारियों को व्यवहार कुशल बनाने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया जाएगा, ताकि वे यात्रियों से बेहतर व्यवहार करें।

रेलवे का अर्थशास्त्र

- यात्री किराए से होने वाली आय में 16.7 फीसदी की वृद्धि हुई है जिससे बजट में 50,175 करोड़ की आमदनी का लक्ष्य।
- माल ढुलाई से होने वाली आमदनी को 1,21,423 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- सकल यातायात प्राप्तियों के 1,83,578 करोड़ रूपये होने का अनुमान।
- मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) के विनियोग को भी 2014–15 के 7,050 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर संशोधित अनुमान में 7,975 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- बजट अनुमान के 92.5 फीसदी की तुलना में परिचालन अनुपात 91.8 फीसदी होने का लक्ष्य रखा गया है जो बजट अनुमान से 0.7 फीसदी का और 2013–14 से 1.8 फीसदी के सुधार को दर्शाता है ।
- 2014–15 के लिए योजना को 65,445 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर संशोधित अनुमान में 65,798 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

बजट में शामिल किए गए पांच उत्प्रेरक

मध्यावधि योजना अपनाना, साझेदारी बनाना, अतिरिक्त संसाधन, व्यवस्था में सुधार, मानव संसाधन को समर्थ बनाना, पारदर्शी मानक स्थापित करना

बजट में किए गए 11 कार्यक्षेत्रों का प्रावधान

- साफ–सफाई–ट्रेनों में लगाए जाएंगे 17000 बायो टॉयलेट।
- बिस्तर–निफ्ट तैयार करेगा आरामदेह बिस्तरों के डिजाइन।
- हेल्पलाइन–चौबीस घंटे, सातों दिन हेल्प लाइन नंबर 138।
- 5 मिनट में टिकट–अनारक्षित यात्रा करने वालों को पांच मिनट में टिकट।
- खानपान–कई और ट्रेनों में ई–कैटरिंग की सुविधा।
- तकनीकी सुविधा–टीटीई को मिलेंगे हैंड हेल्ड टर्मिनल, 400 स्टेशनों पर वाईफाई की होगी सुविधा।
- सीसीटीवी–महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे।
- मनोरंजन–साधारण श्रेणी के डिब्बों में मोबाइल चार्ज सुविधा।
- क्षमता बढ़ोतरी–24 के बजाय 26 सवारी डिब्बे लगाए जाएंगें।
- आरामदेह सफर–ऊपरी बर्थ में चढने के लिए नई सीढियां।
- स्टेशन सुविधा–स्टेशन सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी।

रेल बजट में खास–खास

- रेल यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं।
- योजना परिव्यय 1,00,011 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- यात्री सुविधाओं के लिए आवंटन में 67 फीसदी की वृद्धि।
- पांच मिनट में रेलवे टिकटों के लिए हॉट बटन्स, क्वाइन वैंडिंग मशीनें, भोजन के चयन के लिए ई–कैटरिंग की सुविधा।
- आदर्श स्टेशन योजना के दायरे में 200 अतिरिक्त स्टेशन। बी श्रेणी के स्टेशनों में वाई–फाई की सुविधा।
- महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपनगरीय गाड़ियों के डिब्बों में निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे।
- चिन्हित रेलगाड़ियों में सामान्य श्रेणी के ओर भी डिब्बे जोड़े जाएंगे।
- नौ रेल गलियारों की रफ्तार बढ़ाकर 160 और 200 किलोमीटर प्रतिघंटा की जाएगी।
- चुनिंदा मार्गों पर ट्रेन प्रॉटेक्शन वार्निंग सिस्टम और ट्रेन कॉलिजन एवॉयडेंस सिस्टम लगाया जाएगा।
- 9,400 किलोमीटर के दोहरीकरण/तिहरीकरण/चौहरीकरण की 77 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल: manojshriwastav1982@yahoo.in

सेहत के लिए फायदेमंद भिंडी

—सावित्री यादव

सब्जियों में प्रमुखता से शामिल भिंडी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इसे केवल साधारण सब्जी न मानें बल्कि इसे नियमित रूप से अपने भोजन में शामिल करके सेहत सुधारी जा सकती है। इसका सेवन कालोन कैंसर से बचाता है। इसका विटामिन 'ए' म्यूकस मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है , जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके नियमित सेवन से किडनी की सेहत में सुधार होता है.स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं।

भिंडी देखने में जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें तमाम ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। यह पेट रोगों की रोकथाम से लेकर सौंदर्य वृद्धि तक में कारगर है। इसका फल ही नहीं बल्कि पत्ती एवं इसके पौधे की जड़ भी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। भिंडी की जड़ का चूर्ण बराबर शक्कर के साथ प्रयोग करने से धातु दुर्बलता एवं आमवात में फायदा होता है। इसमें मौजूद विटामिन बी गर्भ को बढ़ने में मदद करता है और जन्मजात विकृतियों को रोकता है। बीजरहित ताजा दो भिन्डी प्रतिदिन खाना श्वेतप्रदर, नपुंसकता, धातु गिरना रोकने में सहायक है। यह गैस्टिक,अल्सर के लिए प्रभावी दवा है। मृदुकारी भिन्डी संवेदनशील बड़ी आंत की सतह की रक्षा करती हैं जिससे ऐठन रूक जाती हैं। इसके सेवन से आंत में जलन नहीं होती है। यह मोटापे को दूर करती है। कई बार शरीर में विटामिन की कमी से ज्यादा खाने का मन करता है। इसलिए भिन्डी में मौजूद विटामिन्स उसकी कमी को दूर कर अनावश्यक भूख को मिटाते हैं।

वास्तव में यह एक ऐसी सब्जी है, जिसे हर इलाके में बड़े चाव से खाया जाता है। भिंडी में प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, फॉस्फोरस, फाइबर आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भिंडी खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है उतनी ही गुणों से भरपूर भी है। भिंडी अक्सर कैरिबियन से लेकर चीन तक के व्यंजनों में उपयोग लाई जाती है और इसकी लोकप्रियता हर समय बढ़ती जा रही है, खासकर जबसे इस सब्जी का इस्तेमाल अचार के रूप में या साइड डिश या सूप की एक सामग्री के तौर पर किया जाने लगा है। इसे इसके तेल के लिए भी उपयोग किया जाता है।

सब्जी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली भिंडी का पौधा जैसे–जैसे बढ़ता है वैसे–वैसे इसमें फल लगते चले जाते हैं। यह करीब एक फीट का होने के बाद फल देने लगता है और करीब चार फीट तक लंबाई हासिल करता है। लंबाई बढ़ने के साथ ही इसमें शाखाएं निकलती हैं और इन शाखाओं में फल लगता है। इसे अलग–अलग इलाके में अलग–अलग नाम से भी जाना एवं पहचाना जाता है। विदेशों में भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे कुछ इलाके में इसे इसे राम तरोई कहते है तो छत्तीसगढ़ में रामकलीय भी पुकारा जाता है। इसकी भरवां और भुजियां दोनों प्रकार से बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है और अरुचि को दूर करती है। इसलिए भिंडी को बहुत पौष्टिक सब्जी माना जाता है। भिंडी से कई प्रकार की रेसिपी जैसे सब्जी, रायता, सूप, कढ़ी आदि बनाई जा सकती

हैं। इससे निकलने वाला रेशेदार चिकना पदार्थ कई प्रकार के रोगों को ठीक करने में मदद करता है। भिंडी खाने से भूख भी बढ़ती है। भिंडी हमारे शरीर में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करती है। इसके साथ–साथ भिंडी शरीर में प्रोबायोटिक्स के विकास में भी मदद करती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और पाचन तंत्र बेहतर होता है। कमजोरी, थकावट महसूस करने वालों के लिए भिंडी ऊर्जावर्धक दवा की तरह काम करती है। डॉक्टरों के मुताबिक भिंडी डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। डिप्रेशन के शिकार लोगों को खाने में कम से कम एक वक्त भिंडी जरूर दी जानी चाहिए।

भिंडी के औषधीय गुण

मधुमेह– मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए खानपान एक बड़ी समस्या होती है। ऐसे लोगों के लिए भिंडी सबसे उपयुक्त है। भिंडी में फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो मधुमेह को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित होती है। भिंडी खून में पहले से मौजूद शूगर के अंश को सोख लेती है और ब्लड शूगर के स्तर को सामान्य बनाने में मदद करती है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में भी मददगार होती है। इससे शूगर का स्तर ठीक रहता है। इसलिए ये डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है।

जोड़ों का दर्द– अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो भिंडी खाएं। भिंडी में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द से राहत पहुंचाता है। इसमें मौजूद लिसलिसा पदार्थ भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भिंडी में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों के लिए लाभकारी होता है। यह जोड़ों को लचीला बनाती है।

अस्थमा– भिंडी अस्थमा के रोगियों के लिए भी काफी लाभकारी साबित होती है। भिंडी में विटामिन 'सी' पाया जाता है, जो अस्थमा के लक्षण को पनपने से रोकता है। इसके अलावा भिंडी फेफड़ों में सूजन और गले में खराश से राहत दिलाने में भी फायदेमंद है। ऐसी स्थिति में अस्थमा रोगियों को हर हाल में भिंडी का सेवन करना चाहिए।

नेत्र रोग– भिंडी नेत्र रोग में भी काफी फायदेमंद है। जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं उन्हें भिंडी खाने से काफी फायदा मिलता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन 'ए' आंखों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। खाने में यदि भिंडी शामिल कर ली जाए तो आंखों की रोशनी तो दुरुस्त होगी ही, आंखों से संबंधित कई अन्य समस्याएं भी ठीक होती हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भिंडी मोतियाबिंद के जोखिम को भी कम करती है, हालांकि भारत में अभी इस पर शोध जारी है।

सौंदर्य वृद्धि– भिंडी एक ऐसी सब्जी है, जो तमाम बीमारियों को रोकने के साथ ही सौंदर्य वृद्धि में भी कारगर साबित हो रही है। भिंडी में विटामिन 'सी' प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस लिहाज से यह हमारी त्वचा के लिए भी वरदान है। ये चेहरे को कोमल और ग्लोइंग बनाने में सहायक है। इससे चेहरे पर होने वाले पिंपल भी दूर हो जाते हैं। त्वचा को पिंपल फ्री बनाना हो या चेहरे को चिकना और चमकदार बनाना हो तो भिंडी का भरपूर प्रयोग करें।

स्वस्थ बाल– भिंडी न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाती है बल्कि हमारे ऊपरी सौंदर्य को भी निखारती है। यह चेहरे की चमक लौटाने के साथ ही बालों को भी स्वस्थ रखती है। रूखे बाल टूट कर गिर रहे हो अथवा बेजान लग रहे हो, इन सारी समस्याओं का इलाज है भिंडी। बालों को बेहतर बनाने के लिए भिंडी को उबालें, जब वह एकदम पतली हो जाए तो उसमें नींबू निचोड़ कर बालों में लगाएं। इससे बालों की कंडीशनिंग हो जाएगी और बाल सिल्की और स्मूथ बन जाएंगे। यह प्रयोग सप्ताहभर करने के बाद असर दिखने लगता है।

पेट रोग– भिंडी में मौजूद रेशे हमारे पेट के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। यह हमारी आंतों के लिए फिल्टर का काम करती है। यह पेट के पित्त, अम्ल और कोलेस्ट्रॉल को बांध देती है, जिससे आंत को नुकसान नहीं पहुंचता। भिंडी आंतों की खराश को भी दूर करती है। इसलिए पेचिश या गैस की समस्या में भी भिंडी काम आती है। भिंडी शरीर में एसिड को भी बेअसर बनाती है और पाचनतंत्र के कवच के रूप में सुरक्षा करती है।

मूत्र जलन– भिंडी पेशाब की जलन को दूर करती है। इसे खाने से पेशाब खुलकर और साफ आता है। इसलिए पेशाब की जलन होने पर भिंडी का सेवन करना चाहिए। करीब पखवाड़े भर नियमित सेवन करने से मूत्र जलन की समस्या समाप्त हो जाती है।

धात रोग– भिंडी का फूल 2 तोला पीस कर पावभर गाय के मट्ठे में मिलाकर पीने से गिरती हुई धात बंद हो जाती है। ऐसे लोगों को यह प्रयोग करीब माह बाद फिर दोहराना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज का सेवन न करें, जिससे पेट में कब्ज हो।

सुजाक– भिंडी सुजाक रोग में भी फायदेमंद है। एक तोला मिश्री को तीन तोला भिंडी की जड़, सफेद इलायची, काली मिर्च को एक साथ घोटकर लें। इसके बाद इसे पखवाड़े भर नियमित रूप से सेवन करने से फायदा मिलता है। ऐसे रोगियों को सब्जी में भी भिंडी का सेवन करना चाहिए।

किचन में भिंडी की दखल

औषधीय गुणों से भरपूर होने की वजह से आज हर गृहिणी

की पहली पसंद भिंडी बनी हुई है। किचन में तमाम सब्जियों के साथ ही भिंडी की मौजूदगी अनिवार्य रूप से दिखती है। इसकी अलग–अलग तरीके से तमाम रेसिपी बनाई जा सकती हैं। कुछ लोग इसे मसालेदार तरीके से तैयार कर स्वाद लेते हैं तो कुछ लोग बिना मसाले के। जहां तमाम सब्जियां बिना मसाले के स्वादिष्ट नहीं होती हैं वही भिंडी बिना मसाले के स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए कारगर बनी हुई है। भिंडी से तैयार रेसिपी को आप चाहें तो फुल डाइट में ले सकते हैं और आप चाहे तो इसे स्टार्टर के तौर पर परोसें या स्नैक्स के रूप में, हर तरह से इसका स्वाद लाजवाब होगा।

कुरकुरी भिंडी

कुरकुरी भिंडी को बनाने के लिए किसी खास तरह के मसाले आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। बस किचन में मौजूद कुछ मसालों के जरिए ही स्वाद लिया जा सकता है। कुरकुरी भिंडी तैयार करने के लिए पहले भिंडी को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। यदि आपके पास 500 ग्राम भिंडी है तो इसके लिए चार चम्मच बेसन, चार चम्मच कार्न फ्लोर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर एवं आधा चम्मच चाट मसाले की जरूरत पड़ेगी। फिर भिंडी को काट लें। कटी हुई भिंडी में सभी मसाले मिलाएं। मसाले मिलने के बाद भिंडी को कुछ देर के लिए रख दें। फिर उसमें कार्न फ्लोर और बेसन मिला लें। इसके बाद कड़ाही गरम करके धीमी आंच में फ्राई करें। इसे तब तक फ्राई करते रहें जब तक इसका रंग ब्राउन न हो जाए।

मसालेदार भिंडी

यदि आपके पास 500 ग्राम कच्ची भिंडी है और इसकी मसालेदार सब्जी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए पांच चम्मच तेल, एक चम्मच जीरा, आधा–आधा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाले की जरूरत पड़ेगी। चार हरी मिर्च एवं बारीक कटे हुए धनिया के अलावा स्वादानुसार नमक डाला जाता है। इसे तैयार करने के लिए भिंडी को अच्छी तरह धो लें। धुली हुई भिंडी के डंठल काट दें । यदि भिंडी ज्यादा लंबी हो तो इसे छोटे–छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर कढ़ाई में तेल डाल कर गरम करें। जीरा डाले और इसे ब्राउन होने तक भुने। फिर धीमी आंच पर सभी मसाले भिंडी में मिलाकर ऊपर से नमक डाल दें। फिर धीमी आंच में पांच मिनट तक भुने। भिंडी को 2 मिनट ढकने के बाद ढक्कन खोल दें। जब भिंडी पक जाए तो ऊपर से धनिया डाल दे। फिर इसे गर्मा–गर्म सर्व करें।

भिंडी की सादी सब्जी

भिंडी की सादी सब्जी बहुत ही आसान है। आधा किलो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए दो हरी मिर्च, एक चम्मच तेल एवं स्वादानुसार नमक की जरूरत पड़ती है। ऊपर से एक चम्मच काली मिर्च और काला नमक डाल दिया जाए तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। सादी भिंडी की सब्जी तैयार करने के लिए भिंडी को अच्छी तरह धोकर छोटा–छोटा काट लें। फिर तेल गरम करके उसमें सीधे भिंडी का छौंक लगाएं। ऊपर से काली मिर्च एवं नमक डालकर सर्व करें।

पंजाबी भिंडी मसाला

भिंडी की सब्जी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसमें पंजाबी भिंडी मसाला का तो अलग ही स्वाद है। यदि आपके पास एक किलो भिंडी है तो दो प्याज, दो हरी मिर्च, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कटी अदरक, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, सात से 10 कली लहसुन एवं दो चम्मच तेल एवं स्वादानुसार नमक की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए भिंडी को अच्छी तरह धोकर कपड़े से पोंछ दें। फिर पैन मे 2 टेबल स्पून तेल डालकर गरम करें। तेल गर्म होने के बाद उसमें भिंडी को तेल मे डाल कर थोड़ी देर गरम करें। जब भिंडी तल जाए तो उन्हें अलग बर्तन मे निकाल लें। अब प्याज, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और लहसुन को काट लीजिए और मिक्सर में इन सभी को पीस कर पेस्ट बना लें। पैन मे तेल डाल कर गर्म करें। जीरा डालकर हल्का ब्रॉउन होने तक भुनें। फिर मसाले के पेस्ट को पैन मे डाल कर हल्का ब्रॉउन होने तक भुनें। इसके बाद सभी मसालों को डालकर भूनें। इसके बाद भिंडी डाल दें। ऊपर हल्दी पाउडर डालने के बाद मिला दें। इसके बाद स्वादानुसार नमक का बुरकाव करें। बस गर्मागर्म पंजाबी भिंडी मसाला सर्व करें।

भरवां भिंडी

आधा किलो भरवां भिंडी तैयार करने के लिए दो सौ ग्राम तेल, दो चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच गर्म मसाला, एक चम्मच अमचूर, एक चम्मच कुटा धनिया, एक छोटी गांठ कद्दूकस से कसी अदरक,बारीक कटी दो प्याज एवं नमक की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह धोकर कपडे से पोंछ लें। अब भिंडी को बीच में से लंबाई में काटकर बीज और गुदा निकाल लें। फिर मसालों को इनके बीच भर दें। कढ़ाई में घी गरम करके हिंग से छौंक लगाकर प्याज को सुनहरा होने तक तल लें। अब मसाला भरी भिंडियों को धागे से लपेटकर प्याज 'हींग' के छौंक वाले तेल में डालकर अच्छी तरह तल लें। थोड़ी देर बाद कढ़ाई को आंच से उतार लें। अब आपकी स्वादिष्ट भरवां भिन्डी तैयार है। इसे सर्व करें।

(लेखिका शोधार्थी हैं)

सफलता की कहानी

बहुफसली खेती ने बदली किसान की तकदीर

–दिव्या श्रीवास्तव

खेती में नई तकनीक अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ी-सी सावधानी बरतने की और लगन के साथ तकनीक सीखने की। कृषि वैज्ञानिकों की ओर से बताई जाने वाली नई तकनीक के जरिए बहुफसली चक्र अपनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ खेती में मुनाफा होगा बल्कि आप दूसरे किसानों के चहेते भी बन सकते हैं। कुछ इसी फंडे पर कार्य कर रहे हैं किसान सुमेश साहू। स्नात्तक की शिक्षा हासिल करने वाले सुमेश आज खेती से न सिर्फ खुद स्वावलंबी हैं बल्कि अपने आसपास रहने वाले तमाम किसानों को भी स्वावलंबी बना रहे हैं।

बहुफसली तकनीक से खेती करते किसान अपनी तकदीर बदल सकते हैं। इसके लिए बहुत अधिक खेत की भी जरूरत नहीं होती है। बस जरूरत है लगन एवं मेहनत की। तमाम किसान ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत करके कम खेत में अभी अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान उन तमाम लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उदाहरण बने हैं, जो यह कहते हुए खेती को छोड़ रहे हैं कि इतने कम रकबे में गुजारा कैसे होगा। ऐसे ही एक किसान हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सुमेश साहू। इन्होंने अपनी कर्मठता के दम पर खेती के क्षेत्र में झंडा गाड़ दिया है। आज स्थिति यह है कि कम क्षेत्रफल और कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने की इनकी तकनीक को पूरे छत्तीसगढ़ के किसान अपना रहे हैं। इन्हें बहुफसली खेती के लिए कई पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। सुमेश ने अपनी चुस्त एवं दुरुस्त कार्यप्रणाली के जरिए यह साबित कर दिया कि समृद्ध किसान बनने के लिए सैकड़ों एकड़ खेत की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो कड़ी मेहनत और उन्नत तकनीक की। उन्नत तकनीक से खेती की जाए तो छोटे किसान भी समृद्ध हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम कोकड़ी निवासी प्रगतिशील किसान सुमेश साहू बताते हैं कि उनके परिवार के लोग हमेशा खेतीबाड़ी से ही जुड़े रहे। उनके पास मात्र चार एकड़ खेत हैं। वह पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेती में काम करते हुए पले-बढ़े। लेकिन उस वक्त खेती में उतनी भी उपज नहीं हो पाती थी कि पूरे परिवार का भरण-पोषण हो सके। इस वजह से पढ़ाई भी अधिक नहीं कर सके। जब वह बड़े हुए तो उनके पिता ने खेती को घाटे का सौदा बताते हुए पढ़ने-लिखने के बाद नौकरी करने की सलाह दी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने लगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसी तरह स्नात्तक तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए। फिर परिवार के खर्चे का बोझ बढ़ा। तय किया कि खेती से कमाई करें, लेकिन परिवार के लोगों को यह मंजूर नहीं था। उनका सीधा-सा जवाब था कि पीढ़ियों से खेती होती रही है। खेत भी ज्यादा नहीं हैं। ऐसे में परिवार का खर्च खेती के भरोसे नहीं उठाया जा सकता है। पिता ने रोजगार तलाशने की सलाह दी। पहले तो अपने गांव के आसपास रोजगार तलाशते

रहे, लेकिन कोई कामधंधा नहीं मिला। फिर शहरों की ओर जाने का मन बनाया। कुछ समय के बाद दोस्तों के साथ शहर गए। यहां कामधंधा शुरू किया, लेकिन मन नहीं लगा। एक शहर से दूसरे शहर भ्रमण करते रहे, लेकिन मन हमेशा खेती में लगा रहता था। अपने गांव और अपने गांव के लोगों से दूर रहकर काम करना मन को नहीं भा रहा था। हमेशा खेत और अपने आसपास रहने वाले लोगों की कमी खलती रहती थी। यही वजह थी कि शहर में मन लगा नहीं। सुमेश बताते हैं कि दोस्तों ने भी समझाया कि खेती के बारे में सोचना बंद कर दें और मन लगाकर काम करे, लेकिन उनका मन तो हमेशा खेती में ही लगा रहता था। वह सोचते रहते कि आखिर खेती को फायदे का सौदा कैसे बनाया जाए। कई बार सब्जी की खेती करने का मन करता तो कई बार तालाब खुदवा कर मछली पालन का मन भी बना, लेकिन जब अपने खेती के रकबे की ओर ध्यान देते तो मन मसोस कर रह जाना पड़ता। उस समय संसाधन भी नहीं थे। खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। काफी सोचने–विचारने के बाद तय किया कि गांव में मौजूद चार एकड़ खेत पर ही मेहनत करेंगे। खेत में मेहनत करके अधिक से अधिक उपज पैदा करेंगे। इसी विचार को लेकर गांव लौटे। यह भी सोचा कि अगर खेती में सफल नहीं हुए तो फिर शहर चले आएंगे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई।

सुमेश बताते हैं कि शहर की कंपनियों में आठ से 10 घंटे काम करना पड़ता है। जबकि गांव में किसान अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा तीन–चार घंटे ही काम करते हैं। ऐसे में उन्होंने मन बनाया कि यदि कंपनियों की तरह ही खेत में भी आठ घंटे का वक्त लगाया जाए तो कुछ न कुछ करिश्मा जरूर होगा। क्योंकि खेती अपनी मर्जी की है। इस वजह से लोग सुबह दो घंटे और शाम को दो घंटे ही खेती में काम करते हैं बाकि वक्त दूसरे कामों में लगाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि खेती में भी उसी तरीके से मेहनत करने की जरूरत है, जैसे कंपनियों में नौकरी के वक्त की जाती है। साथ ही खेती को परंपरागत तरीके से करने के बजाय नई तकनीक के जरिए करने की जरूरत है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ वह शहर छोड़कर गांव लौट आए। सुमेश बताते हैं कि जब वह शहर से गांव लौटे और खेती करने का अपना फैसला सुनाया तो परिवार के लोग नाराज हो गए। उनका कहना था कि खेती तो हमेशा से ही घाटे का सौदा रही है। ऐसे में यहां खेती करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मन तो खेती में ही लग रहा था। मैंने अपने मन की बात मानी और खेती की नई तकनीकों को जानने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से राय–मशविरा लेने लगा। कृषि विभाग जाकर सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली।

यहां से मिलने वाली जानकारी के आधार पर खेती की शुरुआत की। खेती की लागत कम करने के लिए नाडेप खाद और वर्मी कंपोस्ट का स्वयं निर्माण करने लगे। अपने खेत में इसी खाद का प्रयोग करने से कई फायदे हुए। एक तो रासायनिक खाद से अनुपजाऊ हो रही मिट्टी बच गई। दूसरे, इसकी लागत भी कम हो गई। तीसरा फायदा यह हुआ है कि वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए उनके पास तमाम किसान आने लगे। खेती के आधुनिक तौर–तरीके अपनाने वाले सुमेश कहते हैं कि छोटे किसानों को छोटी जोत से निराश होने की जरूरत नहीं है। वे मानते हैं कि यदि छत्तीसगढ़ के छोटे और सीमांत किसान मेहनत और लगन से उन्नत खेती करें तो वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। कृषि और उद्यानिकी विभाग इसमें पूरा सहयोग दे रहा है। सुमेश अपने उत्साहवर्धन और सहयोग के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि वे आज जो कुछ भी हैं उसमें कृषि विभाग की योजनाओं, सलाहों और सरकार द्वारा दी गई मदद का बड़ा योगदान है। वह बताते हैं कि तकनीकी तौर पर खेती करके कम लागत में मुनाफा कमाने की वजह से उन्हें ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पूरे इलाके के लोग उन्हें प्रगतिशील किसान के रूप में जानते एवं पहचानते हैं यही उनके लिए बड़ी उपलब्धि है।

वर्मी कंपोस्ट से भी कर रहे हैं कमाई

सुमेश साहू बताते हैं कि वह वर्मी कंपोस्ट से भी कमाई कर रहे हैं। वह बताते हैं कि तमाम लोगों में यह भ्रम है कि वर्मी कम्पोस्ट में बदबू आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाद तैयार होने के बाद उसमें बदबू आनी बंद हो जाती है। यह डेढ़ से दो माह के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें 2.5 से 3 फीसदी नत्रजन, 1.5 से 2 फीसदी फॉस्फोरस और 1.5 से 2 फीसदी पोटाश पाया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार व गुणवत्ता में भी बढ़ोत्तरी होती है। एक किग्रा. भार में 1000 से 1500 केंचुएं होते हैं। इसे खेत में प्रयोग किए जाने से इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव, एन्जाइम्स, विटामिन तथा वृद्विवर्धक हार्मोन प्रचुर मात्रा में पौधे को

मिल जाते हैं। वर्मी कम्पोस्ट वाली मिट्टी में भू–क्षरण कम होता है तथा मिट्टी की जलधारण क्षमता में सुधार होता है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने वाले किसानों की खेती में लागत कम हो जाती है। इसे तैयार करने के लिए किसान को कोई अतिरिक्त चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस घर पर रहने वाले जानवरों के गोबर एवं घास–फूस, कूड़ा– करकट से ही इसे तैयार किया जा सकता है। सुमेश बताते हैं कि इस खाद को तैयार करने के बाद वह अपने खेत में भी प्रयोग करते हैं। जो खाद बच जाती है उसे आसपास के किसानों को बेच देते हैं।

परंपरागत खेती छोड़ अपनाई नई तकनीक

सुमेश बताते हैं कि पहले परंपरागत तरीके से वर्षा आधारित धान की खेती ही की जाती थी। रबी सीजन में गेहूं बोया जाता था। जब वह कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में आए तो बताया कि खेत के लिए पानी का इंतजाम होना चाहिए। पैसे की भी कमी थी। ऐसे में नलकूप लगवाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सरकार की ओर से योजना चल रही है। फिर सरकारी योजनांतर्गत नलकूप खुदवाया और बैंक से कर्ज लेकर खेतों की फेंसिंग की। इससे उन्हें धान की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली। खरीफ एवं ग्रीष्म दोनों मौसम में धान की खेती करने से भूमि का उपजाऊपन कम होने लगा था तथा ट्यूबवेल का जलस्तर भी घटने लगा था। यह एक नई समस्या थी। इस समस्या को लेकर दोबारा कृषि विभाग के अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने सब्जी की खेती करने की सलाह दी। साथ ही एकल खेती के बजाय बहुफसली तकनीक अपनाने की बात कही। अधिकारियों की सलाह पर फसल चक्र परिवर्तन किया और अपने खेतों में कतार बोनी कर चना एवं सरसों लगाया। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई बल्कि मिट्टी की उर्वराशक्ति बनाए रखने में भी मदद मिली।

कम जोत में अधिक कमाई

सुमेश बताते हैं कि कम खेती होने के बाद भी अपनी आमदनी से संतुष्ट हैं। आधुनिक पद्धति से कृषि कर और फसल चक्रण को अपनाकर कम जोत में भी वह अच्छी कमाई कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की सलाह पर सुमेश एक एकड़ में सब्जी और एक एकड़ में गन्ने की फसल ले रहे हैं। इन खेतों में वे अंतरवर्तीय फसलों के रूप में दलहन और मक्का भी उगाते हैं। सब्जियों की सिंचाई वे ड्रिप पद्धति से करते हैं जिससे पानी की काफी बचत होती है।

खेती का अर्थशास्त्र

खेती का अर्थशास्त्र समझाते हुए सुमेश बताते हैं कि खरीफ मौसम में साढ़े तीन एकड़ खेत में धान, गन्ना और सब्जी की उन्नत खेती करके करीब 3,30,000 रुपये की कमाई कर ली। इसी प्रकार रबी के मौसम में गेहूं, चना और सब्जियों की खेती कर करीब दो लाख की कमाई कर ली। गर्मी के मौसम में आमतौर पर खेत खाली छोड़ दिया जाता है। ऐसे में हमने तय किया कि खेत को खाली नहीं रखेंगे। हमने गर्मी के मौसम में खाली खेत में मक्के की खेती की। इससे करीब 40,000 रुपये की कमाई हुई। साथ ही खेतों की मेड़ों में आम, अमरूद और अनार के पेड़ लगा दिए। ऐसे में जब ये पेड़ बड़े हुए इनसे फल भी मिलने लगा। ऐसे में खेती से लागत निकालने के बाद उनके पास करीब दो से ढाई लाख की सालाना आमदनी होनी लगी। इतने पैसे से परिवार का खर्च आसानी से चल रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। घर भी बना लिया है। किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं हो रही है।

अब किसानों को सिखाते हैं तकनीक

सुमेश खेती के जरिए खुद आत्मनिर्भर बनने के बाद अपने आसपास के किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जुट गए हैं। वह किसानों को तकनीक सिखाते हैं और उन्नतशील खेती के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुमेश बताते हैं कि उनके पास इलाके के तमाम किसान आते हैं और कम लागत में मुनाफेदार खेती के गुर सीख कर जाते हैं। जब तमाम किसान उनके पास आते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है। क्योंकि इतने दिनों में उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, वह खुद के साथ ही दूसरों के भी काम आ रहा है। वह किसानों को खेती करने के साथ ही वर्मी कंपोस्ट की खेती करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। सुमेश बताते हैं कि आगे उनकी योजना है कि औषधीय खेती की जाए। इसके लिए वह कृषि वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क में हैं। पिछले दिनों राजधानी में आयोजित प्रशिक्षण में भी इस बावत हिस्सा लिया था। अब वह यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि औषधीय खेती करते हैं तो तैयार उत्पाद कहां बिकेगा। यदि उत्पाद बिकने के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाती है तो यह पता करेंगे कि लागत के अनुरूप मार्किट में किस दाम में उनकी एलोवेरा अथवा अश्वगंधा आदि फसल बिकती हैं। यह हिसाब लगाने के बाद औषधीय खेती की शुरुआत करेंगे।

(लेखिका किसान क्लब की सदस्य हैं।)
मोबाइल— 09125571010
ई–मेल : divyashriwastav@gmail.com

हमारे आगामी अंक

मई, 2015	– गांवों में पेयजल
जून, 2015	– ग्रामीण पर्यटन
जुलाई, 2015	– गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं
अगस्त, 2015	– गांवों की बदलेगा तस्वीर 'मेक इन इंडिया'

आम बजट 2015–16 की मुख्य विशेषताएं

- भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के पथ पर प्रशस्त।
- कमजोर वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश विकास संकेतक उन्नति के मार्ग पर।
- दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और दोहरे अंकों की विश्वसनीय आर्थिक विकास दर हासिल की गई।
- सौ दिनों के भीतर 12 दशमलव पांच करोड़ परिवारों को वित्तीय मुख्यधारा में शामिल किया गया।
- स्वच्छ भारत अभियान न सिर्फ स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार का एक कार्यक्रम है बल्कि यह भारत के पुनर्निर्माण आंदोलन का रूप ले चुका है।
- मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत से कम रखने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति प्रारूप समझौता।
- सभी के लिए आवास के तहत शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ आवास, 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सड़क संपर्क की मूलभूत सुविधा।
- आजीविका के लिए परिवार से कम से कम एक सदस्य को रोजगार।
- 2020 तक ऑफ–ग्रिड सौर ऊर्जा सहित शेष 20 हजार ग्रामों का विद्युतीकरण।
- 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से भारत को विश्व के विनिर्माण केन्द्र में परिवर्तित करना।
- युवाओं में रोजगार सृजन के लिए उनमें उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहन और विकास।
- पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का देश के अन्य भागों की तरह ही विकास करना।
- सरकार सकल घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत की दर पर राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने के लिए कृतसंकल्प।
- कृषि उत्पादन हेतु दो महत्वपूर्ण निर्णायक कारकों मृदा और जल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
- 'परंपरागत कृषि विकास योजना को पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाएगी।
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना।
- वर्ष 2015–16 के लिए आठ दशमलव पांच लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य।
- ऋण देने में अंतरजातीय और अंतर–जनजातीय उद्यमों को वरीयता।
- गांवों में फैले 1,54,000 उपस्थित केंद्रों वाले डाक नेटवर्क की सामान्य वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- केवल 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये के दुर्घटना, जन्म, मृत्यु, जोखिम को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना।
- सड़कों और रेल मार्गों के लिए परिव्यय में तीव्र वृद्धि।
- 20,000 करोड़ रुपये के वार्षिक प्रवाह से राष्ट्रीय निवेश और अवसरंचना निधि की स्थापना की जाएगी।
- प्लग और प्ले मोड में प्रत्येक 4000 मेगावाट वाली 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं।
- सोना खरीदने के लिए विकल्प के तौर पर सरकारी स्वर्ण बाण्ड स्कीम बनाना।
- भारतीय सोने के सिक्के बनाने की दिशा में कार्य करना जिसके अग्र भाग में अशोक चक्र होगा।
- निर्भया निधि के लिए 1000 करोड़ रुपये।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2022 तक बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य।
- स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में सीएसआर अंशदान के अलावा अंशदानों के लिए 100 प्रतिशत की छूट।
- स्वच्छ पर्यावरण पहलों हेतु वित्तपोषण के लिए कोयला आदि पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन किया गया।
- कृषि उत्पाद की ढुलाई में सेवाकर से छूट जारी रहेगी।

(पसूका से साभार)

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2015–17
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54 / 2015–17
2 अप्रैल 2015 को प्रकाशित एवं 5–6 अप्रैल 2015 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राउत अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना